राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 173

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, रविवार, 1 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ऑस्ट्रेलियाई ओपनर वार्नर के तिहरे शतक से पाकिस्तान पस्त

>> 14

हम भारत के लोग

बंधुआ मजदूरी की बेड़ी तोड़ दूसरों को दिला रहे हक

प्रयागराज : देश को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन बंधुआ मजदूरी प्रथा अब भी समाप्त नहीं हो पाई है। प्रयागराज, उप्र में सैकड़ों परिवार बंधुआ मजदूर हैं। रोशन लाल और रवि शंकर ने बेड़ियों को तोड़ा और अब दूसरों को हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। (पेज-11)

रविवार विशेष

जो अटल व अपरिहार्य है, उसका शोक नहीं मनाता हाथरस

हाथरस : जो अटल व अपरिहार्य है, उसका शोक नहीं करना चाहिए। गीता के इस ज्ञान को उत्तर प्रदेश के हाथरस, जिले के 50 गांवों ने आत्मसात कर दिखाया है। वृद्धों के निधन पर यहां शोक नहीं, उत्सव मनाते हैं। (पेज-11)

जुर्माना घटाने में मनमानी नहीं कर सकते राज्य

अधिकारों की बात ▶ मोटर एक्ट के प्रावधानों पर विधि मंत्रालय ने दी सलाह

कई राज्यों ने लागू नहीं किया है केंद्र सरकार का बनाया नया कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्य सरकारों को मोटर एक्ट के तहत कंपाउंडेबल अपराधों में जुर्माना घटाने का मनमाना अधिकार नहीं मिल सकता है। ये अधिकार राज्य में मोटर अपराध से संबंधित दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर निर्भर हैं। यदि किसी राज्य में खास तरह की सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो उस पर जुर्माना कम नहीं किया जा सकता। राज्य केवल उन्हीं उल्लंघनों में जुर्माना कम कर सकते हैं, जिनमें हादसों का ग्राफ नीचे गिर रहा हो। यह राय विधि मंत्रालय ने मोटर एक्ट पर जुर्माना घटाने के राज्यों के अधिकार के बाबत सड़क परिवहन मंत्रालय को दी है। यह राय गुजरात समेत उन राज्यों के लिए बड़ा झटका है, जिन्होंने अपने यहां बढ़े जुर्माने को लागू करने से इन्कार कर दिया था।

गुजरात के अलावा उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ने एक सितंबर से लागू मोटर एक्ट के बढ़े जुर्मानों को लागू करने से इन्कार कर दिया था। इन राज्यों ने कंपाउंडेबल अपराधों में धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार कम जुर्माना वसूलने का एलान किया था। उत्तर प्रदेश ने भी नए जुर्मानों की अधिसूचना जारी करने में आनाकानी का रवैया अपनाया था। कंपाउंडेबल अपराध ऐसे मामलों को कहा जाता है, जिनमें अदालत के बाहर सुलह-समझौता किया जा सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के रवैये पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य जुर्माना घटा सकते हैं, लेकिन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा जो लगातार बढ़ रही हैं। देश में हर साल पांच लाख दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। गडकरी ने ये बात तब कही थी, जब 2018 के सड़क हादसों के आंकड़े नहीं आए थे। अब ये आंकड़े आ चुके हैं, जिनसे दुर्घटनाओं और मौतों में और बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। गडकरी के बयान के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से राय मांगी थी।

देश में नया मोटर एक्ट लागू होने के बाद लोगों में यातायात नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। (फाइल फोटो)

63 धाराएं एक सितंबर से लागू

मोटर एक्ट पारित होने के बाद सड़क मंत्रालय फिलहाल इसकी 63 धाराओं को एक सितंबर से लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुका है। ये वे धाराएं हैं, जिनके नियम बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन धाराओं के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे लागू किया जाएगा। अभी विभिन्न संगठनों के साथ इससे संबंधित चर्चाएं चल रही हैं।

मोटर एक्ट का मकसद हादसों में कमी लाना

विधि मंत्रालय का स्पष्ट मानना है कि संसद द्वारा पारित कानून को उसकी भावना के अनुरूप ही लागू किया जाना चाहिए। संशोधित मोटर एक्ट 2019 का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है न कि जस का तस रखना या दुर्घटनाओं को बढ़ावा देना।

हादसों के आंकड़ों से तय होगा जुर्माना

- विधि मंत्रालय का कहना है किसी राज्य को कंपाउंडेबल अपराधों में भी जुर्माना घटाने का असीमित अधिकार नहीं मिल सकता। यह उस राज्य में दुर्घटनाओं के आंकड़ों से तय होगा।
- मोटर एक्ट की धारा 174 से लेकर 198 तक के अपराध कंपाउंडेबल श्रेणी में आते हैं, जिनमें कोर्ट में चालान भेजे बगैर पुलिस मौके पर जुर्माना वसूल सकती है।
- उदाहरण के लिए बिना हेलमेट दुपहिया चलाने पर पहली बार 500 रुपये और दुबारा, तिबारा पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने व तीन माह की जेल तक का प्रावधान है।
- इसमें कोई राज्य तभी जुर्माना घटा सकता है, जब वहां बिना हेलमेट दुपहिया चालकों की मौतें कम हो रही हों। यदि मौतें बढ़ रही हैं तो राज्य जुर्माना नहीं घटा सकता।
- इसी प्रकार जिन अपराधों में जुर्माने की राशि न्यूनतम से लेकर अधिकतम तक निर्धारित हो उनमें राज्य को न्यूनतम राशि से कम जुर्माना वसूलने की आजादी नहीं है।

दुष्कर्म के आरोप में उप्र की सूचना आयुक्त और उनके बेटे पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के एक शिक्षिका के आरोप पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जल्द जांच करेगी।

दरअसल, एक प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका की मुलाकात पूर्व छात्र मिलिंद राज से 2016 में हुई थी। 25 मार्च 2016 को मिलिंद ने शिक्षिका को जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने घर पर बुलाया। इसके बाद शिक्षिका को नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोश होने पर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। शिक्षिका ने पति को जानकारी दी तो उसने तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट के जरिए केस करने पर मिलिंद और उनकी मां राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल शादी का झांसा देकर साथ ले गईं और 10 लाख रुपये हड़प लिए। पिछले दिनों सीजीएम ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। गोमतीनगर इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान और घटनास्थल की जांच जल्द की जाएगी।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र का जश्न, 64.44 फीसद वोट पड़े

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र का जश्न मना। जोश और उत्साह के बीच 13 विधानसभा सीटों पर लगभग 64 .44 फीसद वोट पड़े, जो पिछले चुनाव से 1.15 फीसद अधिक है। धुर नक्सल प्रभावित इन इलाकों में लोगों ने भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

सियाचिन में हिमस्खलन से दो जवान शहीद, छह को बचाया

श्रीनगर : समुद्रतल से करीब 18 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में शनिवार को हुए हिमस्खलन में नियंत्रण रेखा के पास गश्त कर रहे दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए। छह अन्य जवानों को समय रहते बचा लिया गया। ज्ञात हो कि 12 दिन पहले हुए हिमस्खलन में चार जवानों समेत छह लोग शहीद हो गए थे।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

अटके घरों के निर्माण से होगी नए वर्ष की शुरुआत

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित स्पेशल विंडो की व्यवस्था अगले दो महीने में काम करना शुरू कर देगी। इकोनॉमिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि हम नए वर्ष का स्वागत अटकी हाउसिंग परियोजनाओं में निर्माण की दोबारा शुरुआत से करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पाकिस्तान में रह चुका था लंदन ब्रिज का हमलावर उस्मान

लंदन : लंदन ब्रिज इलाके में शुक्रवार को चाकूबाजी से दो लोगों की हत्या और तीन अन्य को जख्मी करने वाले आतंकी की पहचान उस्मान खान (28) के रूप में हुई है। किशोरावस्था में वह पाकिस्तान चला गया। उसका परिवार मूल रूप से गुलाम कश्मीर का रहने वाला है। गुलाम कश्मीर में उसने अपनी जमीन पर आतंकी प्रशिक्षण शिविर बना रखा था।

भारत के बगैर आरसेप में नहीं शामिल होगा जापान

- दो टूक कहा, भारत की चिंताओं का निराकरण करें सदस्य देश
- गत दिनों कहा था, समझौते पर दस्तखत से पहले भारत को मना लेंगे

नई दिल्ली, आइएएनएस : आरसेप के मुद्दे पर भारत को जापान का साथ मिला है। जापान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह भारत की भागीदारी के बगैर रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) में शामिल नहीं होगा। जापान ने स्पष्ट किया कि वह आरसेप का हिस्सा तभी बनेगा जब इसमें शामिल देश भारत की चिंताओं का निराकरण कर उसे समझौते का हिस्सा बनाएंगे। जापान द्वारा यह घोषणा दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को प्रस्तावित बैठक से पहले की गई है। आरसेप मुद्दे पर जापान का यह स्टैंड भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए आरसेप से खुद को अलग कर लिया था कि इसमें भारतीय हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। इससे छोटे उद्योगों व कृषि क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई दौर की वार्ता के बाद सरकार ने इस समझौते से खुद को अलग करने का फैसला लिया था। अब जापान के साथ आने से भारत के अलग-थलग पड़ने की संभावना क्षीण हो गई है। भारत द्वारा आरसेप से अलग होने के फैसले के बाद चीन ने कहा था कि भारत के बिना बाकी के 15 देश इस समझौते पर आगे बढ़ेंगे। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी इकोनॉमी हैं। इन दोनों देशों के आरसेप से बाहर रहने की स्थिति में इस समझौते की सफलता पर भी नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि आरसेप प्रस्तावित क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें 10 आशियान देशों के साथ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। इसकी शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान देशों की बैठक के साथ हुई थी।

जापान के इस रुख के मायने

- एशिया की दो बड़ी शक्तियां अगर आरसेप से बाहर रहती हैं, तो यह पूरी कवायद लगभग निरर्थक हो जाएगी
- जापान ने भारतीय चिंताओं के निराकरण का दबाव बनाया है, ताकि आरसेप को प्रासंगिक बनाए रखा जाए
- आर्थिक मोर्चे पर भारत-जापान के कई व्यापारिक हित एक जैसे हैं, लिहाजा जापान के लिए भविष्य में भी भारत बड़ा सहयोगी बना रहेगा
- कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत की यह बड़ी जीत है कि किसी भी बड़े आर्थिक सहयोग संगठन में भारत को दरकिनार करना अब संभव नहीं है

भारत-जापान की मांग, आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाक

नई दिल्ली : भारत और जापान ने पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए उसे खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। भारत और जापान के बीच पहली टू प्लस टू वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। (पेज-3)

करतारपुर पर इमरान के मंत्री ने खोली पाकिस्तान की पोल

- कहा- कॉरिडोर सेना प्रमुख बाजवा के दिमाग की उपज, भारत को देंगे बड़ा घाव
- मंत्री के बयान से भारत के रक्षा विशेषज्ञों की आशंकाओं की पुष्टि हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सिखों के दो अहम गुरुद्वारों को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के पीछे पाकिस्तान की असल मंशा साफ हो गई है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने शनिवार को दावा किया कि करतारपुर कॉरिडोर सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपज है और यह भारत को बड़ा घाव देगा। अब तक यह माना जाता रहा है कि सिखों की भावनाओं के सम्मान में पाक पीएम इमरान खान ने इस कॉरिडोर को खोलने का फैसला किया था। हालांकि, सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्ते बाद जब इमरान ने अचानक करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कही थी, तभी भारत की सुरक्षा एजेंसियां व सुरक्षा विशेषज्ञ पड़ोसी देश की इस दरियादिली को लेकर संशकित हो गए थे। शेख राशिद के बयान ने इस शंका को और मजबूत किया है।

शेख राशिद फाइल फोटो

राशिद ने कहा, 'करतारपुर बार्डर को खोल कर जनरल बाजवा ने भारत को जो घाव दिया है वह उसे लंबे समय तक याद रखेगा। बाजवा ने भारत को बड़ा धक्का दिया है। पाक ने शांति के लिए नया माहौल बनाया है और सिख समुदाय का भरोसा जीता है।' राशिद ने इस बयान से परोक्ष तौर पर करतारपुर कॉरिडोर को पंजाब में अलगाववादी व आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की है। अपने इस बयान से उन्होंने अपने पीएम को झूठा भी करार दिया जो करतारपुर गलियारे का श्रेय स्वयं ले चुके हैं। ज्ञात हो, नौ नवंबर को ही एक भव्य कार्यक्रम में इमरान ने भारत से आमंत्रित कई गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया था। ऐसा नहीं है कि भारत करतारपुर कारीडोर से खालिस्तान आतंकवाद के नए सिरे से शुरु होने के खतरे को लेकर चुप है। पूर्व में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने स्वयं यह बात कही थी। कॉरिडोर को लेकर पाक के साथ जब भारत के विदेश व गृह मंत्रालय के अफसरों की चर्चा शुरू हुई तब ही भारत ने इस बात का जिक्र किया था। समझौते में भी इसका जिक्र है कि श्रद्धालुओं की भावनाएं भड़काने या भारत विरोधी गतिविधियों का कोई काम नहीं होगा, लेकिन पहले दिन जब भारतीय यात्रियों का जत्था वहां पहुंचा तो वहां खालिस्तान संबंधी पोस्टर लगे थे जिन्हें बाद में हटाया गया था। इसी तरह से करतारपुर गलियारे के प्रचार के लिए पाकिस्तान सरकार ने जो प्रचार सामग्री तैयार की थी उसमें एक खालिस्तानी आतंकी का फोटो था जिसे भारत की आपत्ति के बाद हटा दिया गया था।

130 करोड़ भारतीयों का जीवन सशक्त बना रही राजग सरकार : मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के ध्येय वाक्य से प्रेरित और 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से नए जोश से राजग सरकार का 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने और देश के विकास का काम जारी है। अपने दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे करने के अवसर पर मोदी ने 'सिक्समंथ्सऑफइंडियाफर्स्ट' हैशटैग से एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्होंने देश के विकास और सामाजिक सशक्तीकरण को गति दी है और देश की एकता को मजबूत बनाया है। (पेज-3)

महाराष्ट्र में वंदेमातरम से सत्र शुरू न होने पर विवाद

राज्य ब्यूरो, मुंबई

सियासी उठापटक के बाद बनी शिवसेनानीत उद्धव ठाकरे सरकार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। सरकार को 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 169 मत मिले। विश्वास मत के समय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में भाजपा व उसके सहयोगी सदस्यों ने संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया। फड़नवीस ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले सत्र के अंत में चूंकि राष्ट्रगान हुआ था, इसका अर्थ था कि सत्रावसान हो गया था। लिहाजा नया सत्र नियमानुसार राष्ट्रगीत वंदेमातरम के साथ शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि सरकार इसे नया सत्र नहीं मान रही है।

शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही देवेंद्र फड़नवीस ने सदन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं चलने पर आपत्ति जताई। फड़नवीस की आपत्ति गुरुवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में नियमों का पालन न होने को लेकर भी थी। उन्होंने कहा, संविधान में शपथ ग्रहण के लिए शब्दावली तय है। पूरे देश में सरकारें उसी के अनुसार शपथ लेती हैं, लेकिन गुरुवार को सदस्यों ने शपथ लेने के लिए उस शब्दावली में कई और नामों का प्रयोग किया जो संविधान विरुद्ध है। फड़नवीस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का उदाहरण देते हुए कहा, गलत शपथ लेने पर उन्हें पुनः शपथ लेनी पड़ी थी। फड़नवीस ने मंत्रियों को अवैध ठहराते हुए प्रोटेम स्पीकर बदले जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा, ऐसी घटना देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई।

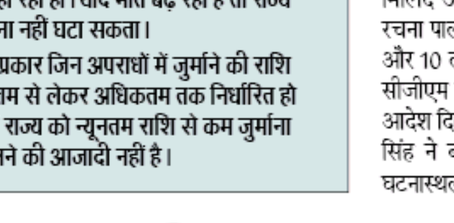

विधानसभा मे शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। एएनआइ

मैं अब तक मैदान में लड़ने वाला आदमी रहा हूं। लेकिन यहां जो व्यवहार देखा, उससे लगा कि मैदान ही सही था। मतभेद सभी के होते हैं, परंतु यहां गलत तरीके से मतभेद रखने की बात हुई।

– उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव न होना संविधान विरुद्ध : फड़नवीस पेज>>4

उप्र में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 190 शिक्षक बर्खास्त

जागरण संवाददाता, आगरा

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से 2004-05 में बीएड की डिग्री लेकर नौकरी करने वाले 190 शिक्षकों (मैनपुरी में 74 व एटा में 116) को बर्खास्त किया गया है। इन शिक्षकों में अधिकांश की बीएड डिग्रियां फर्जी या फिर मार्कशीटें टेंपर्ड पाई गई हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि आगरा की वर्ष 2004-05 की बीएड डिग्रियों में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा था। इस जांच के आधार पर सभी जिलों को फर्जी डिग्रियों से नौकरी कर रहे शिक्षकों की सीडी दी गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग दो साल से इन फर्जी डिग्रीधारियों की जांच में जुटा रहा। जुलाई से शासन के दबाव बनने पर इन शिक्षकों की सूची फाइनल की गई। एटा और मैनपुरी में संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी करने के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में उनका पक्ष सुना गया था। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने सेवा समाप्त करने का फैसला लिया। एटा बीएसए संजय सिंह ने बताया कि 120 में से चार शिक्षकों के कानूनी कार्यवाही की वजह से कार्रवाई लंबित है। मैनपुरी में भी अभी चार शिक्षकों पर कार्रवाई होनी है।

एटा के छात्र की वजह से हुआ था पर्दाफाश : एटा निवासी छात्र सुनील की पहली मार्कशीट में 54 फीसद अंक थे। उसने बीएड सत्र 2004-05 में किया था। यह मार्कशीट गुम हो जाने पर उन्होंने डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाई, उसमें अंक 84 फीसद थे। वर्ष 2013 में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा कि विवि ने मुझे दो तरह की मार्कशीट दी हैं। इसकी जांच हो। हाई कोर्ट ने इसकी जांच एसआइटी को सौंप दी। इसके बाद बड़े घोटाले का राजफाश हुआ। एसआइटी ने 2016 में 5186 फर्जी छात्रों का ब्योरा विवि प्रशासन को सौंप दिया था।

आक्रोश

दरिंदगी के खिलाफ गुस्से की आवाज बनीं अनु

हैदराबाद में हैवानियत से पूरे देश में उबाल, दिल्ली की अनु दुबे ने दिया संसद के सामने धरना, संसद की चौखट पर विरोध दर्ज कराने अकेले पहुंचीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हैदराबाद में युवा महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या और शव को जलाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना ने सात साल पहले दिल्ली की निर्भया के साथ दरिंदों की बर्बरता के जख्मों को हरा कर दिया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। इस दरिंदगी के खिलाफ दिल्ली की एक बेटी का गुस्सा भी फूट पड़ा और वह शनिवार को सुबह-सुबह हाथों में पोस्टर लिए संसद भवन के सामने विरोध करने पहुंच गई। जबकि, हैदराबाद में गुस्साई भीड़ ने उस थाने को दिन भर घेरे रखा, जहां दरिंदों को रखा गया था।

अनु अकेले ही विरोध करने संसद भवन पहुंची थी। उसने जो पोस्टर लिया था, उस पर लिखा था, 'मैं अपने भारत में सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर सकती।' दर्द और गुस्से से भरी अनु ने पोस्टर पर यह भी लिख रखा था कि 'लो जो करना है कर लो, अब डरने का मन नहीं करता।'

हर जगह असुरक्षित हैं बेटियां : अनु का गुस्सा सिर्फ हैदराबाद की घटना को लेकर ही नहीं है। उनका साफ कहना था कि आए दिन देश के किसी न किसी कोने से बेटियों के खिलाफ अत्याचार की खबरें आती हैं, लेकिन कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अनु ने महिलाओं और लड़कियों से यह अपील भी कि उनके साथ कुछ भी गलत होने पर उसे बताएं वो उनके लिए भी प्रदर्शन करेगी।

अब तो घर में भी लगता है डर : मूलरूप से राजस्थान की रहने अनु ने कहा कि अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। इस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

दिल्ली पुलिस ने किया परेशान : अनु ने आरोप लगाया कि संसद भवन के सामने विरोध करने के कारण दिल्ली पुलिस ने परेशान किया। लेकिन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अनु को प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उसे रिहा कर दिया गया। अनु के समर्थन में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल भी थाने पहुंची। उन्होंने अनु के साथ बदसुलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस युवती से बदसलूकी के मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा : इस घटना से सोशल मीडिया पर भी उबाल आया है। दरिंदगी के खिलाफ विरोध का आवाज बनी अनु भी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई और उनकी तुलना पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से होने लगी, जिसने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में पहुंचकर सदस्यों को पर्यावरण को लेकर झकझोर कर रख दिया था।

हैदराबाद में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात के विरोध में शनिवार को संसद भवन के समीप धरना देने पहुंची युवती अनु दुबे मीडिया से बातचीत करते वक्त फूट-फूट कर रोने लगी। ध्रुव कुमार

चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दरिंदे पेज>>5

BYJU'S The Learning App | IAS

PRELIMS MASTER 2020

प्रिलिम्स पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण कवरेज

@7,500/- STARTS 9TH DECEMBER 2019

कार्यक्रम की रूपरेखा

300+ घंटों की सामान्य अध्ययन और CSAT की विस्तृत कक्षाएं

नि: शुल्क प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज (30 TESTS)

अभ्यास हेतु अतिरिक्त 3000+ बहु वैकल्पिक प्रश्नोत्तर

UPSC के विगत 10 वर्षों के प्रश्नपत्रों का विशिष्ट विश्लेषण

समसामयिक विषयों का सम्पूर्ण कवरेज (3 वर्षों का)

भारत-2020 (ईयर बुक), आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का कवरेज

अद्यतन अध्ययन सामग्री

मैपिंग के लिए विशेष कक्षाएं

OFFICE : Shop No. 19, Vardhaman Central Mall, Nehru Vihar, Delhi

Call, SMS or WhatsApp 9205881869

15 उड़ानें शनिवार को कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से डायवर्ट की गई जयपुर और लखनऊ हवाईअड्डों के लिए। सुबह सात से नौ बजे तक दो रनवे की न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 1 दिसंबर 2019

देश का पहला स्वदेशी दंत प्रत्यारोपण उपकरण तैयार

राहुल मानव, नई दिल्ली

देश के दंत चिकित्सकों की अब प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम हो जाएगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (एमएआइडीएस) के प्रोफेसरों ने एक दंत प्रत्यारोपण उपकरण तैयार किया है। उनका दावा है कि यह देश का पहला स्वदेशी दंत प्रत्यारोपण उपकरण है। इससे न सिर्फ भारतीय चिकित्सकों को लाभ होगा, बल्कि दंत प्रत्यारोपण सर्जरी भी सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपकरण को विकसित करने के लिए पत्र लिखकर टीम को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि देश के लोगों को सस्ता उपचार मुहैया कराना ही उनकी सरकार का लक्ष्य है। इस उपकरण से गरीबों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

प्रोजेक्ट के मुख्य जांचकर्ता आइआइटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रो. नरेश भटनागर और एमएआइडीएस के पूर्व निदेशक व गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि इस दंत उपकरण से एक कृत्रिम दांत तैयार किया जा सकेगा, जो कि टाइटेनियम का होगा। यह दांत मसूड़े की जड़ में हमेशा के लिए फिट होने के साथ ही दांत के नीचे मौजूद हड्डियों से भी कुछ ही समय में जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मेक इन इंडिया की तर्ज पर यह उपकरण तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सीएसआइआर ने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआइटीएलआइ) के तहत 10 करोड़ रुपये की फंडिंग की है। सीएसआइआर ने दो वर्ष पहले इसके लिए बिड निकाली थी। इसमें फरीदाबाद स्थित कंपनी इन्नवोल्यूशन मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड (आइएमपीएल) ने बाजी मारी और इस कंपनी की तरफ से वर्ष 2019 में इस उपकरण को बाजार में उतार दिया है। इसकी कीमत अभी 7500 रुपये है।

आइआइटी दिल्ली, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज और सीएसआइआर द्वारा तैयार किया गया डेंटल उपकरण। जागरण

प्रोफेसर नरेश भटनागर। जागरण

कम कीमत पर होगा दंत प्रत्यारोपण : प्रो. नरेश ने बताया कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख दंत प्रत्यारोपण होते हैं। इसके लिए विदेशी दंत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इससे एक दांत के प्रत्यारोपण का खर्च 15 से 25 हजार आता है। वहीं इस उपकरण से करीब आधी कीमत में दांत का प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। यही नहीं सरकारी अस्पतालों में इसका प्रयोग होने पर यह खर्च 5 हजार रुपये से भी कम हो सकता है।

इस तरह हुई शोध की शुरुआत : प्रो. नरेश भटनागर ने बताया कि वर्ष 2005 में हृदय, आर्थोपेडिक सर्जरी और दंत प्रत्यारोपण के लिए विदेशी उपकरणों की निर्भरता पर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद सीएसआइआर ने राष्ट्रीय स्तर पर विकसित परियोजनाओं (एनईपी) के अनुरूप दंत प्रत्यारोपण उपकरण तैयार करने की कोशिश करना शुरू किया। वर्ष 2007 में आइआइटी दिल्ली भी इससे जुड़ गया। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि शोध करने के साथ ही इसके उपकरणों को भी विकसित करना था। फिर दंत प्रत्यारोपण के लिए आइआइटी दिल्ली में टेन एक्स सीएनसी मशीन को स्थापित किया गया, जिससे बेहद ही छोटे दंत उपकरण को तैयार करने में सहायता मिली। उपकरण को तैयार करने से पहले इस तकनीक का पेटेंट वर्ष 2008 में कराया गया। इसके बाद जानवरों पर परीक्षण किया गया। इसमें सफलता मिलने के दो चरणों में 200 लोगों में सफलता पूर्वक दंत प्रत्यारोपण किया गया।

> यह देश का पहला स्वदेशी दंत प्रत्यारोपण उपकरण है। आइआइटी दिल्ली भी वर्ष 2007 में इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया था। सीएसआइआर द्वारा आइआइटी दिल्ली में इस उपकरण को तैयार करने के लिए स्विट्जरलैंड से एक मशीन लाई गई थी। इसकी मदद से इस उपकरण को तैयार किया गया और बाद में इसे एमएसडीटी में लोगों पर भी टेस्ट किया गया। हाल ही में इसका पेटेंट भी मिल गया है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है। इससे देशभर के लोगों को लाभ मिलेगा।
> –प्रो. डॉ. महेश वर्मा, पूर्व निदेशक एमएआइडीएस

इस तरह काम करता है उपकरण

दांत की जड़ पूरी तरह खराब होने पर खराब दांत को निकालकर कृत्रिम दांत लगा दिया जाता है। अभी तक इस कृत्रिम दांत को विदेशों से आयात किया जा रहा है। लेकिन, इस उपकरण से टाइटेनियम का दांत देश में ही तैयार कर प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। मेक इन इंडिया की तर्ज पर तैयार होने वाले यह दांत भविष्य में विदेश में भी निर्यात किए जाने की संभावनाएं हैं। वहीं देश में स्थिति दांतों के करीब 300 अस्पताल हैं। इसमें पढ़ाई कर रहे युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

फेज चार की मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य इस माह होगा शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

फेज चार की परियोजना पर अब दिसंबर में निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। सबसे पहले जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर केशोपुर से पीतमपुरा के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस हिस्से पर एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा 10 स्टेशन बनेंगे। करीब ढाई साल में यह काम पूरा होगा। इस कॉरिडोर पर काम शुरू होने के बाद फेज चार के अन्य कॉरिडोर के काम में गति आएगी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर केशोपुर से पीतमपुरा के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर आवंटित कर चुका है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को काम शुरू करने का आदेश भी दे चुका है। पहले डीएमआरसी ने नवंबर के अंत तक इस कॉरिडोर का निर्माण शुरू कराने की बात कही थी। हालांकि निर्माण शुरू नहीं हो सका है। डीएमआरसी के अनुसार, काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। कॉरिडोर के लिए आवंटित जगह को कब्जे में लेकर उस जगह को घेरने के बाद काम शुरू करने में थोड़ा वक्त लगेगा।

उल्लेखनीय है कि फेज चार में छह मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसकी कुल लंबाई 103.94 किलोमीटर होगी। मौजूदा समय में तीन प्रमुख कॉरिडोर को निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। जिसमें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम, तुगलकाबाद-एरोसिटी व मुकुंदपुर-मौजपुर मेट्रो लाइन शामिल है। डीएमआरसी इन तीनों लाइन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर चुका है। हालांकि इसके भूमिगत कॉरिडोर का काम शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है।

जिन 10 स्टेशनों का काम शुरू होने वाला है, उसमें केशोपुर, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एंक्लेव, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, मधुबन चौक, प्रशांत विहार और नॉर्थ पीतमपुरा शामिल हैं।

तीन प्रमुख कॉरिडोर की लंबाई (किलोमीटर में)

कॉरिडोर	कुल लंबाई	भूमिगत	एलिवेटेड
एयरोसिटी-तुगलकाबाद	20.20	14.61	5.58
जनकपुरी-आरके आश्रम	28.92	7.74	21.18
मुकुंदपुर-मौजपुर	12.55	00	12.55

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द लाएगी बिल

बोले चौबे ▶ डॉक्टरों से मारपीट करने पर सख्त सजा का प्रावधान होगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जल्द ही केंद्र सरकार बिल लेकर आएगी। इसमें डॉक्टरों से मारपीट करने पर सख्त सजा का प्रावधान होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में मेडिकल के छात्रों व जूनियर डॉक्टरों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है और उन्हें भी चिकित्सा नीति का ध्यान रखना चाहिए। चौबे शनिवार को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए यूरोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया के दो दिवसीय सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी संबोधित किया।

अश्विनी चौबे ने डॉक्टरों में संचार कौशल विकसित करने व मरीजों के साथ व्यवहार कुशलता पर जोर दिया, ताकि मरीज व डॉक्टर के बीच विवाद न हो सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया जा रहा है। उसके दायरे में तीमारदारों को भी लाया गया है। रोगी व डॉक्टर के बीच खास रिश्ता होता है। फिर भी कभी-कभी रोगी या तीमारदारों द्वारा डॉक्टरों से मारपीट की घटनाएं होती हैं। इससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है।

अश्विनी चौबे। फाइल

डॉक्टरों से मारपीट करने पर तीन साल से 10 साल तक कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा। यदि कोई अस्पताल में तोड़फोड़ करता है, तो उस क्षति की भरपाई के लिए अलग से जुर्माने का प्रावधान होगा। फिर भी डॉक्टर व मरीज के रिश्ते को बेहतर करने के लिए चिकित्सा जगत द्वारा इस सम्मेलन जैसी पहल होती है तो यह सबसे कारगर रास्ता होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।

अस्पतालों की इमरजेंसी में डॉक्टर बहुत तनाव में होते हैं। वहीं मरीज की गंभीर स्थिति देखकर तीमारदार भी तनाव में होते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास के चलते कुछ लोग गलत कर बैठते हैं। जूनियर डॉक्टर भी कई बार गलती कर बैठते हैं। इसलिए मेडिकल के छात्रों व जूनियर डॉक्टरों को व्यवहार कुशल व संचार में दक्ष बनाना चाहिए।

इस सम्मेलन को सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष व आयोजन समिति के सचिव डॉ. अनूप कुमार, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. अनिल गोयल सहित कई डॉक्टरों ने संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टरों को बताया गया कि इलाज के दौरान मरीजों को सही व पूरी जानकारी देकर कानूनी विवाद से भी बच सकेंगे।

भाजपा और आप के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि भाजपा और आप दिल्ली की लगभग 40 फीसद अनधिकृत कॉलोनियों को तोड़ने का षडयंत्र रच रही है। कांग्रेस इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने का बिल पेश करते समय केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कॉलोनियों की सूची पटल पर नहीं रखी। भाजपा को मालूम है कि कॉलोनियों की सूची सामने आने के बाद लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1976-77 की नीति के अलावा कोई दूसरी नीति मंजूर नही है।

दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सरकार पहले ही केंद्र सरकार से इन कॉलोनियों को नियमित करने की सिफारिश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों की सीमा निर्धारित करने का काम दिल्ली सरकार का है। मुख्य प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा व आप के खिलाफ आंदोलन के पहले चरण में शहरी विकास राज्यमंत्री के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर 2019 की अधिसूचना की धारा 7 के भाग ए में मौजूद प्रावधान अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।

चेक क्लोनिंग कर एम्स के खातों से निकाले 12 करोड़

- दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच में जुटी
- अक्टूबर व नवंबर में निकाले गए रुपये, एसबीआइ ने देशभर में जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के दो अलग-अलग बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने चेक क्लोनिंग कर करीब 12 करोड़ रुपये निकाल लिए। साइबर अपराधियों ने यह रकम एक माह के दौरान मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि शहरों में बैठकर निकाले हैं। एम्स प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्ल्यू), एसबीआइ सहित सीबीआइ में इसकी शिकायत की है। इओडब्ल्यू ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

अक्टूबर और नवंबर में साइबर ठगों ने चेक क्लोनिंग के जरिये एम्स के खाते से 12.44 करोड़ रुपये निकाल लिए। इसमें एम्स के निदेशक के खाते से करीब सात करोड़ रुपये जबकि डीन के नाम वाले खाते से करीब पांच करोड़ रुपये निकाले। बड़ी रकम निकाले जाने का मैसेज आने पर प्रशासन ने एसबीआइ से इसकी जानकारी मांगी। इसमें साइबर अपराधियों द्वारा रकम उड़ाए जाने की बात सामने आई। इस पर एम्स प्रशासन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सहित पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एसबीआइ ने भी इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक की जांच में बैंक यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि ठगी कैसे हुई। नियम के मुताबिक दो लाख से ज्यादा की रकम का चेक पास करने से पहले बैंक इसकी सूचना खाताधारक को देता है। लेकिन, इस मामले में बैंक ने ऐसा नहीं किया। इस घटना के बाद एसबीआइ ने भी देशभर की बैंक शाखाओं में अलर्ट जारी कर दिया है। उन्हें कहा गया है कि एम्स से संबंधित किसी भी चेक का निस्तारण सावधानी से करें।

इधर, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इतनी बड़ी जालसाजी बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। प्रथमदृष्टया इस मामले में बैंक अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी सामने आ रही है। ऐसे में आशंका है कि इस घटना में एम्स या फिर बैंक का कोई कर्मचारी शामिल हो।

सूत्रों के मुताबिक ठगी के इस तरह के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) का दिशानिर्देश है कि तीन करोड़ रुपये से ऊपर की ठगी के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से कराई जाए। इसलिए इसकी जांच के लिए सीबीआइ को भी लिखा गया है। मामला प्रकाश में आते ही बैंक के साथ ही दिल्ली पुलिस की इओडब्ल्यू में इसकी शिकायत दी गई है।

डीसीपी से बदसुलूकी व पुलिसकर्मी से पिस्टल लूटने वालों की हुई पहचान

जासं, नई दिल्ली : तीस हजारी अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी की जांच जारी है। जांच में अब तक करीब 150 वकील, पुलिस सहित अन्य लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में उत्तरी जिला की डीसीपी मोनिका भारद्वाज से बदसुलूकी और उनके ऑपरेटर पुलिसकर्मी संदीप से पिस्टल लूटने वालों की भी पहचान की जा चुकी है। वहीं, कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी करने वाले कई वकीलों का भी पता चल गया है। क्राइम ब्रांच एसआइटी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। चूंकि हाई कोर्ट की तरफ से एक महीने तक किसी भी वकील की गिरफ्तारी पर रोक है। इसीलिए पुलिस ने अभी इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

गत दो नवंबर को पुलिस-वकीलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों की तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। आरोप है कि बीच-बचाव करने आए डीसीपी के ऑपरेटर पर वकील टूट पड़े थे, जिससे उनका कंधा फ्रैक्चर होने के अलावा सिर फट गया था। इसी दौरान उनकी पिस्टल भी लूट ली गई थी। इस संबंध में सब्जी मंडी थाने में पिस्टल लूटने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआइटी ने जिन लोगों से अब तक पूछताछ की है उनसे से अधिकतर लोगों ने बताया कि अफवाह की वजह से कोर्ट में माहौल बिगड़ा था।

निर्भया मामले में आरोपित राम सिंह की खुदकशी पर उठे सवाल

जासं, नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में वर्ष 2013 में आरोपित राम सिंह की जेल में खुदकशी के मामले में तिहाड़ जेल के पूर्व विधि अधिकारी सुनील गुप्ता ने कहा है कि एक छोटे से सेल में जिसमें राम सिंह के अलावा भी अन्य कैदी हों, कोई भला कैसे खुदकशी कर सकता है? उन्होंने अपनी पुस्तक ब्लैक वारंट में लिखा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि राम सिंह की हत्या की गई हो।

सुनील गुप्ता तिहाड़ में 35 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह बताते हैं कि 11 मार्च 2013 की सुबह जब उन्हें इस बारे में पता चला कि राम सिंह ने अपने सेल में फांसी लगा ली है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि राम सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने ध्यान से देखा था। उस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि राम सिंह के शरीर में अल्कोहल के अंश पाए गए थे। सुनील आशंका जाहिर करते हैं कि जब वह नशे में होगा तब उसकी हत्या हुई हो। आखिर जिस कमरे में फर्श और छत के बीच करीब 12 फीट का फासला हो तो कोई कैसे फांसी लगा सकता है। आखिर वह छत तक पहुंचेगा कैसे?

विधानसभा में भाजपा उठाएगी अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन का मुद्दा : विजेंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक देने का मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेता अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में बहस से सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए भाजपा विधायक विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि दिल्ली के 40 लाख लोगों से जुड़े मामले पर चर्चा हो सके। उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि जब लोगों के मकानों की रजिस्ट्री होने लगेगी तब वह केंद्र सरकार की बातों पर विश्वास करेंगे। जबकि केंद्र सरकार 16 दिसंबर से यह काम शुरू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। दिल्ली में कुल 21 सब रजिस्ट्रार है। एक सब रजिस्ट्रार कार्यालय औसतन एक दिन में दस रजिस्ट्री होती है। इस तरह से रोजाना लगभग दो सौ लोगों की रजिस्ट्री होगी। जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की वेबसाइट पर लाखों लोग मालिकाना हक के लिए आवेदन करेंगे। इस हिसाब से दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।

लोगों को अपने मकान की रजिस्ट्री कराने में दिक्कत नहीं हो इसके लिए 40-50 अतिरिक्त काउंटर खोलने की जरूरत है। डीडीए हेल्प डेस्क भी स्थापित कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार लोगों की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रेस वार्ता में विधायक जगदीश प्रधान, पूर्व विधायक अनिल बाजपेयी व प्रदेश मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा मौजूद थे।

भाजपा ने आरक्षित सीटों के लिए तैयार किया प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ ही इन क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आरक्षित सीटों के साथ ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति का समर्थन हासिल करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन होगा जिसमें दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता शामिल होंगे। 12 आरक्षित सीटों पर भाजपा की पकड़ कमजोर मानी जाती है। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए भाजपा रणनीतिकारों ने काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार शाम को प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि है बैठक में 15 दिसंबर तक अनुसूचित जाति से संबंधित अलग-अलग जातियों के सम्मेलन करने का लक्ष्य रखा गया है।

हवा की रफ्तार घटी तो बढ़ गया प्रदूषण

जासं, नई दिल्ली : बारिश के चलते दो दिन तक मिली राहत के बाद शनिवार को एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन में दिल्ली का एयर इंडेक्स 193 दर्ज हुआ, जो कि सामान्य श्रेणी में आता है। शुक्रवार को यह 84 दर्ज हुआ था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार को हवा की रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषक कण एक ही जगह पर ठहर गए। इससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो गई। वहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी दिल्ली में सामान्य श्रेणी में प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। अगले दो दिनों 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। ऐसे में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में जाने की उम्मीद नहीं है। हालांकि रविवार की सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बढ़ रही है सर्दी : मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से वहां से ठंडी हवा दिल्ली में पहुंच रही है। इससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी।

सिग्नेचर ब्रिज पर रंग-बिरंगी रोशनी की होगी व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की पहचान बन चुका सिग्नेचर ब्रिज पर रंग-बिरंगी रोशनी की व्यवस्था रहेगी। होली, दिवाली पर रोशनी के विशेष शो का आयोजन भी किया जाएगा। इसी तरह दो अक्टूबर को ब्रिज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित होगा। इस दिन गांधी जी के चित्र दिखाई देंगे।

दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक विस्तुत योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी निर्धारित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्माण पर लगे प्रतिबंध के हटते ही इस योजना पर काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिज के पूरे 675 मीटर भाग में रंग- बिरंगी रोशनी की जाएगी। ब्रिज के 154 मीटर ऊंचे मुख्य पिलर पर 150 लाइटों का फोकस रहेगा। इन लाइटों को ब्रिज के पास खंभों पर लगाया जाएगा। इसके अलावा मुख्य पिलर के साथ लगे तारों को भी रोशनी से सजाया जाएगा। इस योजना को फरवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, पर्यटकों को मुख्य पिलर पर ले जाने के लिए ब्रिज से यमुना खादर की सतह तक रैंप बनाने का काम करने के लिए कंपनी निर्धारित हो चुकी है। पार्किंग क्षेत्र व कैफेटेरिया के लिए भी कंपनी तय हो चुकी है। यह कार्य भी फरवरी के अंत तक पूरा होगा। बता दें कि वजीराबाद में यमुना नदी पर बना यह बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज 4 नवंबर 2018 को जनता को समर्पित किया गया था।

सिग्नेचर ब्रिज। फाइल

- होली और दिवाली पर रोशनी के विशेष शो का किया जाएगा आयोजन
- दो अक्टूबर को दिखाई देंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र

आयोजन

> जीयो गीता संस्थान द्वारा आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव-2019 में हजारों लोग एक साथ गीता का पाठ करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व प्रताप चंद्र सारंगी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल

लालकिला गीता पाठ से आज होगा गूंजायमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लालकिला रविवार को गीता के सस्वर पाठ से गूंजायमान होगा। जीयो गीता संस्थान द्वारा आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव-2019 में हजारों लोग एक साथ इस धर्मग्रंथ का पाठ करेंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व प्रताप चंद्र सारंगी भी शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। वहीं, महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस अवसर पर अवधेशानंद महाराज, स्वामी परमात्मानंद व साध्वी ऋतंभरा के साथ ही जैन, बुद्ध, सिख व मुस्लिम धर्म के संत मौजूद रहेंगे। खास बात कि 18 मुस्लिम छात्र भी उर्दू में गीता का पाठ कर गंगा-यमुना तहजीब को जीवंत बनाएंगे।

एकदिवसीय भगवत गीता प्रेरणा कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख द्वारा दिया गया प्रवचन केवल उनके शिष्य अर्जुन के लिए नहीं है बल्कि समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए है। भगवान सबके हैं और भगवान सबमें हैं। गीता के माध्यम से मानसिक शांति, मनोबल संवर्धन, कर्तव्यनिष्ठा, ध्येय निष्ठा से लेकर विश्व बंधुत्व, प्रेम, क्षमता, समरसता एवं सकारात्मकता की प्राप्ति होती है। इस आयोजन से सभी श्रद्धालुओं को विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। देश के विभिन्न भागों से आए 1800 अर्चक, धर्म स्थानों के सेवा अधिकारी, पुजारी, कर्मकांडी मौजूद रहेंगे।

लालकिला मैदान में रविवार को आयोजित होने वाले गीता प्रेरणा महोत्सव के लिए तैयार मंच। संजय

लालकिले का लाइट एंड साउंड शो 'राष्ट्रवाद' को होगा समर्पित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- नए शो की स्क्रिप्ट इतिहासकार कपिल कुमार ने तैयार की है।

लालकिले का लाइट एंड साउंड शो जल्द नए अवतार में वापस आ रहा है। अब इसकी स्क्रिप्ट बदली गई है। पहले यह कार्यक्रम मुगल इतिहास पर केंद्रित था, अब यह राष्ट्रवाद को समर्पित होगा। इसमें लालकिले से जुड़ी चीजें बताई जाएंगी। नए शो की स्क्रिप्ट इतिहासकार कपिल कुमार ने तैयार की है। कुमार ने बताया कि नई स्क्रिप्ट का पूरा जोर इस पर है कि लालकिला आखिर भारत की पहचान या राष्ट्रीय स्मारक कैसे बना? इस कार्यक्रम की तकनीक बदली गई है। जिसमें चित्र भी दिखेंगे। लाइट एंड साउंड शो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसका समय करीब एक घंटे का होगा। जनवरी में इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराए जाने की योजना है।

कपिल कुमार कहते हैं कि यह आयोजन राष्ट्रवाद को समर्पित होगा। किस तरह आजादी के लिए कुर्बानियां दी गईं यह भी इस आयोजन का हिस्सा होगा। पहले वाला कार्यक्रम मुगल इतिहास केंद्रित था। वह गलत नहीं था, लेकिन आजकल बच्चे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री लालकिले से ही क्यों झंडा फहराते हैं। यह इस शो में नहीं बताया गया था। नए शो में शाहजहां के वक्त की बातें हैं और उनके बाद की भी।

कपिल कुमार का कहना है कि नए शो में बताया जाएगा कि लालकिला कब और कैसे बना। इसकी वास्तुकला और इसके सांस्कृतिक पहलू पर भी चर्चा होगी। लोगों की रुचि बनाए रखने के लिए यह कहानी भी बताई जाएगी कि कैसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया। यह दर्शाया जाएगा कि नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पगड़ी बदलने के लिए मजबूर किया था, उसमें वह हीरा लगा हुआ था। आगे बहादुर शाह जफर के बारे में बताया गया है। ब्रिटिश आक्रमण की चर्चा भी होगी। लालकिला में करीब डेढ़ साल से लाइस एंड साउंड बंद है।

रेल भवन धरना मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल आरोप मुक्त

जासं, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती सहित अन्य आप नेताओं को रेल भवन के बाहर प्रदर्शन के बाद दर्ज हुए केस से आरोप मुक्त कर दिया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सभी को इस केस से डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। प्रतिबंध के बावजूद धरना देने और लोक सेवक के काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।

अदालत में पुलिस की तरफ से दायर आरोपपत्र में कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं ने जनवरी 2014 में रेल भवन के बाहर धरना दिया था। यह धरना कथित ड्रग बेचने वालों पर रेड न करने के चलते पुलिस के खिलाफ दिया गया था। पुलिस नेआरोपपत्र में कहा गया था कि धारा 144 लागू कर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद धरना देकर इन लोगों ने सरकारी और लोक सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाई गई थी। अब अदालत ने सभी को आरोपमुक्त कर दिया है।

71 वर्ष का हो गया है आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। 1947 में रणवीर स्कूल से रेडियो कश्मीर जम्मू का सफर शुरू हुआ था। मनोरंजन के अलावा यह पाकिस्तान के दुष्प्रचार का भी दे रहा है करारा जवाब

130 करोड़ भारतीयों का जीवन सशक्त बना रही राजग सरकार

मोदी बोले ▶ देश के विकास का काम जारी, बहुत कुछ करना बाकी

- केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे
- मोदी ने 'सिक्समंथ्सऑफइंडियाफर्स्ट' हैशटैग से एक के बाद एक कई ट्वीट कर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई
- कहा, भविष्य में सरकार बहुत कुछ करना चाहती है ताकि देश समृद्ध व प्रगतिशील बन सके

प्रमुख उपलब्धियां
- अनुच्छेद-370 व 35ए का खात्मा
- तत्काल तीन तलाक विधेयक
- मोटर वाहन कानून में संशोधन
- उद्योगों के लिए कर्जमाफी योजना
- बैंकों के विलय का फैसला
- कारपोरेट टैक्स में कमी

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के ध्येय वाक्य से प्रेरित और 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से नए जोश से राजग सरकार का 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने और देश के विकास का काम जारी है।

अपने दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे करने के अवसर पर मोदी ने 'सिक्समंथ्सऑफइंडियाफर्स्ट' हैशटैग से एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्होंने देश के विकास और सामाजिक सशक्तीकरण को गति दी है और देश की एकता को मजबूत बनाया है। मोदी ने कहा कि भविष्य में सरकार और बहुत कुछ करना चाहती है ताकि समृद्ध और प्रगतिशील नए भारत का निर्माण किया जा सके। मालूम हो कि अपने दूसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी ने 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी।

जावड़ेकर बोले, कश्मीर में आतंकवाद निचले स्तर पर : मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद निचले स्तर पर है। अनुच्छेद-370 और 35ए हटने से कश्मीर में शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और सामान्य जीवन व्यवस्थित हो गया है।

जम्मू-कश्मीर के विकास के नए रास्ते भी खुले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश प्रगति की राह पर तेजी से दौड़ रहा है और देशहित में फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन सरकार ने इससे उबरने के प्रयास तेज कर दिए है। सरकार ने बैंकों का विलय, उद्योगों के लिए कर्जमाफी योजना और सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश जैसे बड़े फैसले लिए हैं। इसके अलावा भारत सबसे कम कारपोरेट टैक्स वाले देश के रूप में उभरा है जिससे वैश्विक निवेशकों में उम्मीद जगी है।

राफेल युद्धक विमान और अन्य उपकरणों की खरीद करके पिछले छह महीने में देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं। तत्काल तीन तलाक के खिलाफ विधेयक लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है। हाल में सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या मामले पर आए फैसले को भी सभी समुदायों ने शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं ने दुनिया में भारत की छवि को मजबूत बनाया है। इसके अलावा सरकार लोगों की आदतों में बदलाव लाकर एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने की कोशिश में लगी है।

उप्र में डिग्री कॉलेजों का रिजल्ट तय करेगा सीटें बढ़ेंगी या नहीं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : डिग्री कॉलेजों में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। खासकर ऐसे निजी डिग्री कॉलेज जहां आए दिन कक्षाएं न होने और तरह-तरह की अन्य शिकायतें मिलती हैं। उन पर अब लगाम कसी जाएगी। कॉलेजों के रिजल्ट का मूल्यांकन होगा और ऐसे कॉलेज जहां रिजल्ट खराब है, उन्हें विभिन्न पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 40 फीसद से कम रिजल्ट वाले कॉलेजों की निगरानी होगी। अच्छे रिजल्ट के साथ-साथ इन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकन करवाने के लिए किए गए आवेदन की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। वहीं राजकीय डिग्री कॉलेज व अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को भी नैक मूल्यांकन हर हाल में करवाना होगा, इसके बिना उनकी सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर सभी डिग्री कॉलेजों को नैक से मूल्यांकन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ कॉलेजों को अपने रिजल्ट में सुधार की भी कोशिशें करनी होंगी। ऐसे कॉलेज जिन कॉलेजों का अच्छा रिजल्ट है और उन्होंने नैक से मूल्यांकन करवाया है, उन्हें नए कोर्स शुरू करने और पुराने चल रहे कोर्सेज में सीटें बढ़ाने की अनुमति प्राथमिकता पर भी दी जाएगी। इससे कॉलेजों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अभी प्रदेश में कुल 6531 निजी डिग्री कॉलेजों में से मात्र 306 ने नैक से मूल्यांकन करवाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मेमोरी कार्ड व पेन ड्राइव को साक्ष्य ठहराया

- कहा, किसी आपराधिक मामले में आरोपित को इसकी प्रति पाने का हक
- दुष्कर्म मामले में आरोपित को सामग्री की कॉपी देने से मना कर सकती है कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को निश्चित रूप से दस्तावेज की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आरोपित इस दस्तावेज की कॉपी पाने का हकदार भी है, ताकि वह अपने बचाव की ठीक ढंग से तैयारी कर सके।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के नाते मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्रियां निश्चत रूप से दस्तावेज के रूप में ली जानी चाहिए। यदि किसी आपराधिक मामले में अभियोग इन सामग्रियों पर निर्भर है, तो आरोपी को इसकी क्लोन प्रति दी जानी चाहिए ताकि वह सुनवाई के दौरान अपना प्रभावी बचाव कर सके।'

शीर्ष अदालत ने मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप की याचिका पर यह फैसला दिया है। दिलीप ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक अभिनेत्री के अपहरण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी 2017 के मामले में एक मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड की प्रति मांगी थी।

हालांकि, दो सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दुष्कर्म के मामले में सामग्रियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अदालत आरोपित को उसकी प्रति देने से मना भी कर सकती, ताकि पीड़ित महिला की निजता और सम्मान का उल्लंघन न होने पाए।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि जिन मुकदमों में शिकायतकर्ता/गवाह की निजता या उसकी पहचान जैसे मामले शामिल हैं, उनमें अदालत सुनवाई के दौरान प्रभावी बचाव के लिए केवल आरोपी, उसके वकील या विशेषज्ञ को ही सामग्री मुहैया कराने या अदालत में ही उसे देखने का आदेश दे सकती है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इन सामग्रियों की कॉपी करने या दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ उपाय भी जरूरी हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आरोपित, उसके वकील या आइटी विशेषज्ञ के पास सीमित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हों। उनके पास मोबाइल फोन या ऐसा कोई उपकरण भी नहीं होने चाहिए, जिससे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव की कॉपी या उसकी सामग्रियों की चोरी संभव हो। अदालत ने मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्रियों को 'भौतिक वस्तु' (मैटेरियल ऑब्जेक्ट) मानने से भी इन्कार कर दिया।

बता दें कि फरवरी 2017 में एक अभिनेत्री का आठ आरोपियों ने कथित अपहरण एवं यौन उत्पीड़न किया था। अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के इरादे से इस पूरे कृत्य को फिल्माया गया था। इसके बाद दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था और मामले में आरोपी बनाया गया था। केरल हाई कोर्ट ने दिलीप की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मेमोरी कार्ड या पेन कार्ड को भारतीय साक्ष्य कानून के तहत 'दस्तावेज' नहीं समझा जा सकता और आरोपी को नहीं सौंपा जा सकता।

पाक स्थित आतंकी संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- भारत और जापान के बीच दिल्ली में हुई पहली 'टू प्लस टू' वार्ता
- पाक समर्थित आतंकवाद पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ जापान

जापान के रक्षा मंत्री कोनो तारो (बाएं) ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आरसेप पर जापान के रुख से अवगत कराया। एएनआइ

भारत और जापान ने संयुक्त तौर पर पाकिस्तान को बेहद कड़ा संकेत दिया है। आतंकी संगठनों को पनाह देने के लिए दुनिया भर में कुख्यात पाकिस्तान को लेकर भारत व जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में अहम चर्चा हुई। 'टू प्लस टू' व्यवस्था के तहत हुई इस वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। जापान ने भारत की तर्ज पर ही पाकिस्तान को अपने यहां के आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस व स्थायी कदम उठाने को कहा है। यह पहला मौका है जब जापान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को उसके यहां के आतंकी पनाहगाहों के लिए सीधे तौर पर खरी-खरी सुनाई है।

संयुक्त बयान से स्पष्ट है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों की समान चिंताएं हैं। भारत व जापान ने इस क्षेत्र में सभी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर तरह के नौकाओं और विमानों के निर्बाध तरीके से आवागमन की सुविधा का समर्थन किया है। इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने की भी बात कही है। कहने की जरूरत नहीं कि यहां निशाना इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार करने में जुटे पाकिस्तान को बनाया गया है। लेकिन, संयुक्त बयान में जो बात सबसे ज्यादा भारत की संवेदनाओं को छूता है, वह आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। जापान पहले भी भारत का समर्थन करता रहा है, चाहे चीन के साथ भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम विवाद हो या कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला। जापान ने कभी खुलकर तो कभी चुप रहकर भारत का समर्थन किया है। लेकिन शनिवार को जारी संयुक्त बयान भारत के पक्ष को समझने व उसका समर्थन करने की नई मिसाल देता है।

दोनों देशों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है और इसे विश्व शांति व स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। बैठक में शामिल मंत्रियों ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वे अपने यहां बनाए गए आतंकियों की शरणस्थली को नष्ट करें। सभी देशों से यह आग्रह भी किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके यहां के आतंकी संगठन किसी दूसरे देश में आतंकी हमले नहीं करें।

बताते चलें कि टू प्लस टू वार्ता के दो हफ्ते बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष एबी शिंजो के बीच सालाना शिखर बैठक होनी है। यह संभवतः असम की राजधानी गुवाहाटी में होगी। इन दोनों नेताओं की पिछले वर्ष हुई बैठक में ही विदेश व रक्षा मंत्रियों की बैठक टू प्लस टू व्यवस्था के तहत कराने पर सहमति बनी थी। शनिवार को इसकी पहली बैठक यहां हुई है। इस तरह की व्यवस्था भारत अभी तक सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशीमित्सु और रक्षा मंत्री कोनो तारो शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे थे।

बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। टू प्लस टू बैठक से पहले जापान के दोनों मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने गए। पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की अलग अलग बैठक हुई और उसके बाद संयुक्त तौर पर बैठक हुई। टू प्लस टू वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान से स्पष्ट है कि दोनों देश सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के लिए कितने अहम होने जा रहे हैं। बयान में कहा भी गया है कि अब द्विपक्षीय रक्षा व सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक संबंधों को और गहरा बनाने का काम तेजी से होगा।

भारत, जापान संबंध हिंद-प्रशांत की समृद्धि के लिए अहम : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत का जापान के साथ संबंध हिंद-प्रशांत में शांति, समृद्धि और स्थिरता की उसकी दृष्टि का एक प्रमुख हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी ने यह टिप्पणी जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशीमित्सु और रक्षा मंत्री कोनो तारो के साथ एक बैठक के दौरान की। बैठक में मोदी ने कहा कि भारत-जापान के बीच रिश्तों का सर्वांगीण विकास दोनों देशों के लोगों के साथ ही क्षेत्र और विश्व की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी ने यह भी कहा कि वे अगले महीने प्रधानमंत्री एबी शिंजो के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर रहे हैं।

तारो ने किया हिंडन अड्डे का दौरा : जापानी रक्षा मंत्री कानो तारो ने शनिवार को हिंडन स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे का दौरा किया। वहां उन्हें भारतीय वायुसेना की संगठनात्मक संरचना और इसकी संचालन क्षमताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया। जापानी रक्षा मंत्री और उनके साथ आए शिष्टमंडल का स्वागत एयर मार्शल डी चौधरी एवं वायुसेना के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने की। अधिकारियों ने बताया कि जापानी रक्षा मंत्री को वायुसेना की संठनात्मक संरचना और संचालन क्षमताओं का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया।

नागरिकता विधेयक पर पूर्वोत्तर राज्यों को मनाने में जुटा केंद्र

- पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ गृह मंत्री ने की बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों, छात्र निकायों और नागरिक समाज समूह के नेताओं के साथ विधेयक की रूपरेखा पर चर्चा की।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विभिन्न सांसदों ने शिरकत की। इससे पहले असम के मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ट्वीट कर बताया था कि, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर त्रिपुरा और मिजोरम के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के साथ चार घंटे तक चर्चा की। वह शनिवार को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडलों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।' नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रस्तावित संशोधन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने की बात कहता है, भले ही उनके पास कोई उचित दस्तावेज न हों। विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के कड़े विरोध के मद्देनजर ही गृह मंत्री ने शुक्रवार और शनिवार को सिलसिलेवार बैठकें कीं। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल भी केंद्र सरकार के कदम को गलत बताने के साथ ही विरोध प्रदर्शनों को हवा देने में जुटे हुए हैं।

अमित शाह फाइल फोटो

तुरंत जमा करें ट्रांसजेंडर छात्रा का नामांकन फॉर्म : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंग स्वास्थ विश्वविद्यालय को दिया निर्देश
- 28 नवंबर थी एडमिशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख

कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस टी चक्रवर्ती की अदालत ने पश्चिम बंग स्वास्थ विश्वविद्यालय को शनिवार दोपहर दो बजे तक ट्रांसजेंडर छात्रा आलिया शेख का एडमिशन फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर थी। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित छात्रा आलिया शेख ने बताया कि विवि की ओर से उसे दिए गए प्रवेश परिपत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोई कॉलम ही नहीं था। विवि की ओर से उसे तीसरे लिंग वर्ग में प्रवेश लेने को कहा गया। विवि पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आलिया को प्रवेश तो मिल सकता है। लेकिन यहां फिलहाल ओबीसी वर्ग की सुविधा नहीं है।

ज्ञात हो, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर आलिया शेख ने याचिका दायर की मांग की थी कि विवि के प्रवेश फॉर्म में पुरुष व महिला के साथ तीसरे लिंग का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। वह यहां से क्लीनिकल साइकोलॉजी से एमफिल करना चाहती है। विवि ने बताया कि प्रबंधन ने इस बाबत विकल्प उपलब्ध करा दिया है।

क्लीनिकल साइकोलॉजी संभाग में 12 सीट हैं। एक सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। आलिया के वकील ने कहा, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को भी ओबीसी में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता विवि (सीयू) को निर्देश दिया है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार तीसरे लिंग के छात्रों के लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए। इसके जवाब में विवि पक्ष ने बताया कि सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की है।

आरएसएस का मुखौटा है भाजपा : गहलोत

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- कहा, संघ को खुद सीधे ही राजनीति में उतर जाना चाहिए
- सीएम बोले, भाजपा का ग्राफ उतरा, नेता घमंड में

गुजरात के अहमदाबाद शहर में कांग्रेस की ओर से आयोजित जन वेदना सम्मेलन को संबोधित करते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। (एएफपी)

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा केवल मुखौटा है। सत्ता की चाबी आरएसएस के हाथों में है। देश की अर्थव्यवस्था खराब है। सरकार का ग्राफ लगातार गिर रहा है फिर भी भाजपा नेता घमंड में हैं। गहलोत ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी।

महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की बदहाली, गिरती अर्थव्यवस्था व महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गुजरात कांग्रेस की ओर से अहमदाबाद में आयोजित जन वेदना सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने भाजपा की अगुआई वाली केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जो चाहता है भाजपा वही करती है। संघ को खुद सीधे ही राजनीति में उतर जाना चाहिए।

महाराष्ट्र व हरियाणा के चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा की हकीकत समझ गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा पहले ही सत्ता से बाहर हो चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जैसे फैसले कर भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उस समय आगाह किया था कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी आज वही बात सच साबित हुई।

शराबबंदी पर गुजरात के सीएम को घेरा : अशोक गहलोत ने गुजरात में शराबबंदी को विफल बताते हुए एक बार फिर रूपाणी सरकार पर हल्ला बोला। गहलोत ने कहा कि मेरे बयान को लेकर गुजरात के सीएम नाराज हो गए ओर हमला भी बोला। शराबबंदी के मुद्दे पर मैं गलत हूं तो इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा रूपाणी इस्तीफा दें। गहलोत ने रूपाणी को रिमोट से चलने वाला सीएम बताया।

रूपाणी बोले, राजस्थान में शराववंदी करके दिखाएं

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गहलोत को जवाब देते हुए उन्हें चुनौती दी कि वे राजस्थान में शराबबंदी करके दिखाएं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई वाघाणी ने कहा, कांग्रेस के साथ न तो जन है और न ही वेदना। कांग्रेस नेता अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। वाघाणी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के विकास का विरोध किया है। नर्मदा बांध का मामला हो या राज्य के विकास का विषय, कांग्रेस कभी भी जनता के हित में खड़ी नहीं हुई। इसलिए आज उनकी ऐसी हालत हो गई है।

अगस्ता मामले में मिशेल से जेल में होगी पूछताछ

नई दिल्ली जागरण संवाददाता

रतुल पुरी की अर्जी पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कारोबारी रतुल पुरी की जमानत अर्जी पर शनिवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। विशेष अदालत ने पुरी की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। रतुल पुरी की कंपनी मोजर बेयर से जुड़े करीब 354 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में पुरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी गिरफ्तार किया गया। रतुल पुरी फिलहाल न्यायिक हिरासत मे जेल में है।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुख्य आरोपित क्रिश्चियन मिशेल से सीबीआइ एक बार फिर तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 5 और 6 दिसंबर के लिए इसके लिए अनुमति दी है। सीबीआइ ने रक्षा सौदे से जुड़े एक अन्य मामले में मिशेल से पूछताछ करने के लिए अर्जी दायर की थी। केंद्रीय एजेंसी 2008 में भारतीय सेना के लिए हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे की जांच कर रही है। इस मामले में सेना के तत्कालीन बड़े अधिकारी ब्रिगेडियर वीएस सैनी पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप की भी जांच चल रही है।

विमान घोटाले में यास्मीन कपूर के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली : विमान घोटाले में आरोपित कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की करीबी यास्मीन कपूर और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन दिनेशालय (ईडी) ने आरोपपत्र दायर किया गया है। कपूर को मनी लांड्रिंग के तहत आरोपित मानते हुए आरोपपत्र दायर किया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आरोपपत्र की स्वीकृति देते हुए दस्तावेजों की जांच के लिए 7 जनवरी 2020 की तारीख तय की है।

नायडू बोले

उत्तराखंड के रुड़की के पास कुंजा बहादुर गांव में बोले उपराष्ट्रपति, मातृभाषा पर दिया जोर, कहा- अधिकारों के साथ लोग अपना कर्तव्य भी समझें

देश से छिपाया गया आजादी का असली इतिहास

जागरण टीम, देहरादून

हरिद्वार में शनिवार को कुंजा बहादुर गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते वेंकैया नायडू। जागरण

जीडीपी में आई गिरावट तात्कालिक

देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस) के दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आई गिरावट तात्कालिक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वाले देश में आज कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शुमार नहीं है। इसकी हमें चिंता करनी होगी।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि आजादी के असली इतिहास को छिपाया गया है। जरूरत है कि नई पीढ़ी तक इसकी जानकारी पहुंचे। इसके लिए आजादी के नायकों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को महान काम बताते हुए नायडू ने देशवासियों की सराहना करते हुए कहा, अयोध्या पर आए फैसले ने फिर साबित किया कि शांति व सौहार्द हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, शांति के लिए भी शक्ति का होना जरूरी है।

शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रुड़की के पास कुंजा बहादुर गांव में शहीद राजा विजय सिंह स्मारक एवं कन्या शिक्षा प्रसार समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ज्ञात हो, कुंजा रियासत के राजा विजय सिंह ने वर्ष 1822 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका और 1824 में लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके 44 अन्य साथियों को फांसी पर लटका दिया था।

उपराष्ट्रपति ने कहा, कुंजा बहादुरपुर के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कहा कि वह देश में कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक कुंजा बहादुरपुर गांव के गौरवमयी इतिहास के बारे में बताएंगे। मातृभाषा को अपनाने पर जोर देते हुए नायडू ने कहा कि भाषा भावना से जुड़ी होती है। अंग्रेजी या दूसरी भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान जरूरी है। वहीं, शासन- प्रशासन सरकारी गजट, ऑर्डर, लेटर को अंग्रेजी में जारी करता है, ये मातृभाषा में भी होने चाहिए। भाषाएं जिंदा रहेंगी तो संस्कृति जिंदा रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारों की बात करें, लेकिन कर्तव्य के बारे में भी सोचें। कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उप राष्ट्रपति को कुंजा बहादुरपुर के इतिहास से जुड़ी पुस्तक भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार कुंजा बहादुर गांव में शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण कराएगी।

इकबाल मिर्ची मामले के दो आरोपितों को जमानत

मुंबई, प्रेट्र : विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इकबाल मिर्ची से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले के दो आरोपितों को जमानत दे दी जबकि दो अन्य की अर्जी ठुकरा दी।

मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के न्यायाधीश पी. राजवैद्य ने शनिवार को मिर्ची के कथित सहयोगी हारुन यूसुफ और हुमायूं मर्चेंट की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इन दोनों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने हालांकि रंजीत बिंद्रा और रिंकू देशपांडे की जमानत मंजूर कर ली। बिंद्रा मिर्ची की संपत्ति के सौदे में ब्रोकर था और देशपांडे के माध्यम से उसने अपना कमीशन लिया था। आरोपितों की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है। संगठित अपराध से पैसे बनाए गए थे जिसका आतंकियों की आर्थिक मदद और नशीले पदार्थ के कारोबार में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। इसकी जांच की जा रही है। ईडी ने दावा किया कि इस मामले के अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े होने के संकेत सामने आ रहे हैं। ईडी ने चारों को अक्टूबर में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था।

कह के रहेंगे माधव जोशी

नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र का जश्न

उत्साह ▶ पहले चरण में 64 .44 फीसद मतदान, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी थीं कतारें

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

छिटपुट घटनाओं को छोड़ सभी 13 सीटों पर शातिपूर्ण ढंग से मतदान

जागरण ब्यूरो, रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र का जश्न मना। जोश और उत्साह के बीच 13 विधानसभा सीटों पर लगभग 64.44 फीसद वोट पड़े, जो पिछले चुनाव से 1.15 फीसद अधिक है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें दिखने लगीं। कतार में पुरुषों से अधिक महिलाएं दिखीं, लेकिन पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले 18 से 19 वर्ष के युवाओं में जबरदस्त उत्साह था।

पुलिस-प्रशासन के चुस्त इंतजाम के बीच घोर नक्सल इलाकों में भी लोगों ने बेखौफ होकर मताधिकार का प्रयोग किया। तमाम मतदान केंद्र ऐसे भी थे, जिन पर दोपहर तीन बजे के बाद भी बड़ी-बड़ी कतारें लगी रहीं। गुमला में घाघरा स्थित कठठोकवा पुल के पास नक्सलियों ने मामूली विस्फोट कर चुनाव में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। विस्फोट इतना हल्का था कि घटनास्थल पर कुछ मिट्टी भर उड़ी। इससे पहले लोहरदगा के कौआडांड़ गांव में शुक्रवार रात नक्सलियों ने एक मतदान केंद्र के भवन के पास भी मामूली विस्फोट किया था, इससे भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा सभी जगह निर्बाध मतदान संपन्न हुआ है। उन्होंने मतदान फीसद बढ़ने पर संतोष जताया।

झारखंड के लोहरदगा के सेन्हा स्थित मतदान केंद्र पर शनिवार को इवीएम खराब होने के कारण मतदान रोकना पड़ा। फिर भी उत्साहित मतदाता मताधिकार का उपयोग करने के लिए डटे रहे। जागरण

पिस्तौल लहराते कांग्रेस प्रत्याशी सह पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी। सौ. सोशल मीडिया

कांग्रेस प्रत्याशी ने लहराई पिस्तौल

डालटनगंज के चैनपुर में भाजपा और कांग्रेस समर्थक एक-दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भिड़ गए। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पिस्तौल लहराया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे के निर्देश पर पुलिस ने त्रिपाठी से पिस्तौल जब्त कर उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उधर पलामू के ही हुसैनाबाद में आजसू प्रत्याशी कुशवाहा शिवपूजन महतो ने एक मतदान केंद्र पर हंगामा किया।

189 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद : पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान सम्पन्न होने के बाद 189 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इनमें 15 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। इन सीटों पर मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दूबे, केएन त्रिपाठी, भानुप्रताप शाही, कमलेश सिंह समेत कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है।

कहां कितना प्रतिशत मतदान

सीट	वर्ष 2014	वर्ष 2019
चतरा	53.62	56.59
गुमला	60.73	67.3
बिशुनपुर	66.92	69.8
लोहरदगा	67.75	71.47
मनिका	59.77	62.66
लातेहार	66.17	67.2
पांकी	65.72	64.1
डालटनगंज	64.70	63.9
विश्रामपुर	61.31	61.6
छतरपुर	59.63	62.3
हुसैनाबाद	62.31	60.9
गढ़वा	67.81	66.04
भवनाथपुर	68.16	67.34
कुल	63.29	64.44

पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव न होना संविधान विरुद्ध : देवेंद्र फड़नवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने विश्वासमत से पहले पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव नहीं किए जाने को भी संविधान विरुद्ध करार दिया। उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि किस डर से सरकार ने विश्वास मत से पहले गुप्त मतदान के जरिये पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव नहीं करवाया? फड़नवीस ने सदन की कार्यवाही पर ये सवाल उठाते हुए कहा कि जिस सदन में संविधान के नियमों का पालन नहीं होता, वे उस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। यह कहकर भाजपा और उसके सहयोगी निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 114 सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। भाजपा इस मामले की शिकायत राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट से करने पर भी विचार कर रही है।

भाजपा और उसके साथी विधायकों के बहिष्कार के बाद कांग्रेस सदस्य अशोक चह्वाण ने ठाकरे सरकार के पक्ष में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। राकांपा के दो सदस्यों नवाब मलिक व जयंत पाटिल और शिवसेना सदस्य सुनील प्रभु ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके बाद एक-एक सदस्य ने अपना नाम बोलकर उद्धव सरकार के पक्ष में होने की घोषणा की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के दो, माकपा का एक और उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे का एक विधायक तटस्थ रहा।

उद्धव ठाकरे के विश्वास मत पेश किए जाने के दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस (दाएं से दूसरे) के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। एएनआइ

प्रोटेम स्पीकर ने दिया भाजपा को जवाब : फड़नवीस के सभी सवालों पर मोर्चा संभाला स्वयं प्रोटेम स्पीकर दिलीप वलसे पाटिल ने। उन्होंने कहा कि विश्वास मत की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में विश्वास मत पारित करवाने का निर्देश दिया था। जबकि विश्वास मत जीतने के बाद भगवा साफा पहने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फड़नवीस के उठाए सवाल पर कहा, 'हां मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज और अपने माता-पिता के नाम पर शपथ ली है। यदि यह अपराध है तो मैं बार-बार करूंगा।' उद्धव ने आगे कहा कि जो अपने देव और माता-पिता को नहीं मानता, वह इस जग में रहने लायक नहीं है। सीएम ने कहा, 'यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों और साधुओं का है, जिनकी शपथ लेकर हमने काम संभाला है, उन्हें हमारे कार्यों पर गौरव हो, हमें ऐसे काम करना है।'

आज सुलझेगा महाराष्ट्र में स्पीकर का मसला

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) कौन होगा, यह रविवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष अधिवेशन में तय हो जाएगा। इस पद के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने नामांकन किया है।

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस के हिस्से में और उपाध्यक्ष का पद राकांपा के हिस्से में आया है। कांग्रेस ने इस पद के लिए अपने सदस्य नाना पटोले को उम्मीदवार बनाया है। जबकि भाजपा ने अपने विधायक किसन कथोरे को। महाराष्ट्र विधानमंडल के नियमानुसार यदि विधानसभाध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक लोग उम्मीदवार हों तो फैसला गुप्त मतदान के जरिये होता है। यदि बनी बनाई परिपाटी के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही चलती तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता, फिर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती, तत्पश्चात स्पीकर का चुनाव होता, उसके बाद विश्वास मत पर मतदान होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस परिपाटी में ही परिवर्तन कर दिया। उसके निर्देशानुसार प्रोटेम स्पीकर के चुनाव बाद सदस्यों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद सीधे विश्वासमत की प्रक्रिया पूरी की गई।

शुरुआती दौर में भाजपा को उम्मीद थी कि यदि पूर्णकालिक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान से होगा तो उसके उम्मीदवार को अजीत पवार समर्थक कुछ राकांपा विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों के मत मिल सकते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार की पूरी तरह घर वापसी हो चुकी है।

कांग्रेस विधायक नाना पटोले। उन्होंने शनिवार को स्पीकर के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया। प्रेट्र

कांग्रेस ने नाना पटोले और भाजपा ने किसन कथोरे को बनाया उम्मीदवार

राकांपा ने अभी तय नहीं किया उपमुख्यमंत्री

राकांपा ने अपने हिस्से में आए उपमुख्यमंत्री पद के लिए अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल के अनुसार इसका फैसला अब शीतकालीन अधिवेशन के बाद होगा। इस पद की दौड़ में अजीत पवार ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसलिए अब वह या उनके समर्थक विधायक शक के दायरे में आने वाला कोई कदम उठाने से बचेंगे।

कमल पर बैठकर घर आएंगी लक्ष्मी : स्मृति

जेएनएन, घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम) : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिनकी आंखों पर भ्रष्टाचार का चश्मा होता है, उन्हें विकास का सूरज नहीं दिखता। लक्ष्मी कमल पर बैठकर घर आएंगी, तीर कमान पकड़ कर नहीं आतीं। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल की दो सीटों, बहरागोड़ा और घाटशिला, से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। चाकुलिया के केएनजे मैदान और मऊभंडार के ताम्र प्रतिभा मैदान में आयोजित सभाओं में उनके निशाने पर विपक्ष रहा। चाकुलिया में कुछ देर बांग्ला में भाषण देकर महिलाओं का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड का पिछले पांच वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। झारखंड में अब लोगों को गढ्ढों भरी सड़कों से नहीं गुजरना पड़ता है। सरल व सपाट सड़के भाजपा ने बनवाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने आतंकियों को मुहंतोड़ जवाब दिया। अनुच्छेद 370 खत्म कर देश को एक सूत्र में बांधा है।

ओवैसी ने दी एनआरसी लागू करने की चुनौती

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादु मुस्लेमीन (एआइएमआइएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि वह पूरे देश में एनआरसी लागू करे। ओवैसी शनिवार को मानगो के गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़ेगा। अगर सरकार में दम है, तो पहले एनआरसी लागू करे और इसके बाद नागरिक संशोधन बिल लाए। उन्होंने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मजलिस आपके साथ है। ओवैसी ने कहा कि अब कांग्रेस में दमखम नहीं रहा। उसने तीन तलाक बिल का समर्थन किया था। कांग्रेस शिवसेना से निकाह करती है और मजलिस पर भाजपा की बी टीम होने का इल्जाम लगाती है। यह आरोप साबित करता है कि मजलिस देश की राजनीति में अपना मुकाम बना रही है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान बड़ी उपलब्धि : चौबे

राज्य ब्यूरो, रांची

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले चरण की 13 सीटों के 4,892 मतदान केंद्रों में से 4,162 मतदान केंद्र संवेदनशील और अतिसंवेदनशील थे। शांतिपूर्ण मतदान कराना बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,269 चुनाव कर्मियों को दो दिन पहले ही मतदान केंद्र या कलस्टर तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। 203 मतदान केंद्रों के 440 कर्मियों की हेली ड्रापिंग की गई। इसमें चार हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। उनके अनुसार, अधिसंख्य मतदान केंद्रों से मतदान संपन्न कराकर चुनाव कर्मी वापस लौट गए हैं। कुछ मतदान कर्मी कलस्टर में रोके गए हैं। 1,226 मतदान केंद्रों के चुनाव कर्मी रविवार को अपने जिला मुख्यालय में पहुंचाए जाएंगे। इसमें भी पांच हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा।

84.22 फीसद दिव्यांग मतदाताओं ने किए वोट : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, कुल चिह्नित 49 हजार मतदाताओं में 84.22 फीसद ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिव्यांगों की सुविधा के लिए 7,106 स्वयंसेवक तैनात किए गए थे। 2952 व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। 1,108 दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक लाने तथा उन्हें वापस पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी।

टोकन व्यवस्था फेल, आयोग नाराज : मतदाताओं को लंबी कतारों से बचाने के लिए पहली बार इस विधानसभा चुनाव में मतदान में टोकन व्यवस्था किए जाने की योजना फेल हो गई। अधिसंख्य मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें देखी गईं। मतदाताओं को बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसपर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अगले चरण के विधानसभा क्षेत्रों में इसकी गहन समीक्षा करने तथा इसे पूरी तरह लागू करने का भरोसा दिलाया।

घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंपर मतदान

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान में कई रोचक रूझान सामने आए। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंपर वोटिंग हुई तो कम नक्सल क्षेत्र में मतदान प्रतिशत घटा भी। पांच विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पूर्व की तुलना में मतदान प्रतिशत घटा है, तो आठ क्षेत्रों में बढ़ा है। घोर नक्सल प्रभावित मनिका, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, बिशुनपुर, चतरा, विश्रामपुर व छतरपुर में मतदान प्रतिशत का बढ़ना इस बात का शुभ संकेत है कि नक्सलियों के प्रति ग्रामीणों का मोहभंग हुआ है। वहीं, पांकी, डालटनगंज, हुसैनाबाद, गढ़वा व भवनाथपुर में मतदान प्रतिशत का घटना सरकारी मशीनरी का फेल होना व विकास के दावे को झुठलाने का संकेत दे रहा है।

कहां बढ़ा और घटा मतदान प्रतिशत : अगर 13 सीटों पर ओवर ऑल मतदान प्रतिशत का आकलन किया जाए तो गत चुनाव की तुलना में एक फीसद की बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष की तुलना में चतरा में तीन फीसद, गुमला में सात फीसद, विशुनपुर में दो फीसद, लोहरदगा में चार फीसद, मनिका में तीन फीसद, लातेहार में एक फीसद व छतरपुर में तीन फीसद मतदान बढ़े हैं।

वोट से दिया नक्सलियों को करारा जवाब

जेएनएन, रांची

झारखंड में पहले चरण के चुनाव में बुलेट पर बैलेट की जीत देखी गई। लोगों ने वोट की ताकत से नक्सलियों को करारा जवाब दिया। लाल आतंक के गढ़ लातेहार के लुकुइया गांव में भी सुबह के साढ़े छह बजे ठिठुरती ठंड के बावजूद ग्रामीण वोटिंग के लिए राजकीय मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र की ओर रुख करते देखे गए। गृहणियां भी घरेलू कामकाज छोड़कर मतदान के लिए कतारबद्ध दिखीं।

आठ दिन पूर्व नक्सलियों ने लुकुइया मोड़ के पास निशाना बनाकर चार पुलिसकर्मियों की जान ले ली थी। आशंका थी कि नक्सली हमले का असर इस गांव में वोटिंग पर पड़ेगा। लेकिन गांव में 72 फीसद वोटिंग हुई। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के घाघरा और निरासी पंचायत के हेसराग, सेरेंगदाग एवं सुदूरवर्ती इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टर चिपका कर लोगों को मतदान नहीं करने का फरमान सुनाया था, लेकिन वोटरों ने नक्सलियों के फरमान को अनसुना कर बेखौफ होकर जबरदस्त मतदान किया। कतार में काफी देर से खड़े लोगों के चेहरे पर भी मतदान की खुशियां झलक रही थीं।

डालटनगंज नगर निगम क्षेत्र के गणेश लाल अग्रवाल हाई स्कूल में सुबह से ही मतदाताओं की कतार दिखने लगी थी। शहरी क्षेत्र होने के कारण कतार कभी लंबी नहीं हुई लेकिन भीड़ छटी भी नहीं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात नहीं थे। शाहपुर से कुछ आगे बनने पर लोगों का उत्साह कुछ और बयां कर रहा था। रिक्शा चला कर गुजारा करने वाले विजय ने बताया कि इस बार बदलाव होगा। कोसों दूर रामगढ़ प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की धुन पर थिरकता लोकतंत्र दिखा। कभी नक्सलियों की दखलअंदाजी पर मतदान करने वाले लोगों में खौफ का कहीं नाम नहीं था। आगे सरहुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में दर्जनों की संख्या में लोग खड़े दिखे और पहले 3 घंटे में ही 30 प्रतिशत मतदान का आंकड़ा पार कर चुका था। यहां मतदान करने पहुंचीं सविता बहुत खुश थीं कि सत्ता के गठन में उसकी भी भूमिका है। यहीं पर मौजूद रामप्रवेश बदलाव को लेकर मुखर थे। मतदान को लेकर नक्सली डर की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि वह पहले की बात थी। अब तो सब अपने अपने मन से वोट देते हैं। आगे उलडंडा में बदलाव की बयार को महसूस किया जा सकता था। कुछ दूर आगे कुंडपानी गांव में निर्माणाधीन स्टेडियम के बगल में स्कूल को मतदान केंद्र बनाया गया है। गढ़वा के रमकंडा और भंडरिया इलाकों में कहीं भी नक्सलियों का भय नहीं दिखा।

शहीद हुए एएसआइ के गांव में भी बंपर मतदान

लातेहार के चंदवा में हाल ही में नक्सली हमले में शहीद हुए सहायक अवर निरीक्षक (एएसआइ) संतोष उरांव के गांव के लोगों ने अपने निकट के मतदान केंद्रों पर शनिवार को जमकर मतदान किया। शहीद सुकरा उरांव की पत्नी लीलमुनी देवी ने घाघरा के मतदान केंद्र पर मतदान किया।

अलबर्ट एक्का की भूमि पर भी लोगों ने खूब दिखाया जोश

अमर शहीद परमवीर अलबर्ट एक्का की जन्मभूमि गुमला के जारी में लोगों ने जमकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। सुबह से ही लोग जारी, गोविंदपुर, जरदा आदि मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार में खड़े थे। हालांकि, लोगों को इस बात का अफसोस था कि परमवीर की पत्नी बलमदीना एक्का लोकतंत्र के इस पावन पर्व में शिरकत नहीं कर सकीं। वह हाथ-पैर से लाचार हैं।

उपचुनाव में भाजपा की हार के लिए सांसदों पर उठ रही अंगुली

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- बंगाल में सांगठनिक कार्यों में सांसदों की गतिविधियां कम होने का आरोप
- निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर भी उठ रहे सवाल

राज्य की तीन विधानसभा सीटों खड़गपुर, कालियागंज व करीमपुर के उपचुनाव में भाजपा को मिली हार को लेकर पार्टी में जोरदार चर्चा चल रही है। पार्टी में कोई हार की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता बल्कि शीर्ष नेताओं से लेकर निचले स्तर के नेता एक-दूसरे की कमियां दिखा रहे हैं। चुनाव परिणाम पक्ष में होने के लिए भाजपा का एक वर्ग अपनी पार्टी के सांसदों पर ही अंगुली उठा रहे हैं। उसका मानना है कि सांसद निर्वाचित होने से पहले पार्टी नेता अपने इलाके में पार्टी के कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय थे। सांसद बनने के बाद वे दिल्ली में अधिक समय दे रहे हैं। यदि वे पहले जैसा ही स्थानीय स्तर पर सांगठनिक कार्यों में सक्रिय रहते तो उपचुनाव का परिणाम कुछ और होता। सांसद एवं नेताओं के साथ ही निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए, कालियागंज में भाजपा के 9 पंचायत सदस्य हैं। पिछले एक साल में, उनकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी संख्या में आरोप प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमा किए गए हैं, लेकिन राज्य नेतृत्व उन्हें भय के कारण कुछ नहीं कह सका। भय यह था कि कुछ बोलने से कहीं ये लोग तृणमूल कांग्रेस में न चले जाएं। इसी तरह, करीमपुर और खड़गपुर के कई नेताओं पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। पार्टी नेतृत्व एनआरसी के साथ वाममोर्चा एवं कांग्रेस के गठबंधन को भी पार्टी के हार के कारणों में देख रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव में हार होने के बावजूद पार्टी वर्ष 2021 के पहले संभल जाएगी। कालियागंज विधानसभा सीट रायगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। यहां की सांसद देवश्री चौधरी केंद्रीय राज्यमंत्री हैं। स्थानीय कई नेताओं की शिकायत है कि मंत्री बनने के बाद देवश्री का कालियागंज पर ध्यान कम हो गया।

नवोदय विद्यालय की छात्रा की मौत पर प्रियंका ने लिखा योगी को पत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा की मौत की जांच कराने की मांग की है। प्रियंका का कहना है कि राज्य में लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस मामले की जांच जरूरी है। पत्र में प्रियंका ने मुख्यमंत्री से लड़की के पिता और उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना से जुड़ी सच्चाई को सामने लाने के लिए इस मामले में तुरंत व निष्पक्ष कार्रवाई करने की जरूरत है। प्रियंका ने 16 सितंबर को छात्रा की मौत को हत्या बताते हुए कहा है कि वह छात्रावास में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि माता-पिता की गैरमौजूदगी में प्रशासन द्वारा गैरकानूनी तरीके से लड़की के शव का जलप्रवाह कर दिया गया।

अपने पत्र में प्रियंका ने लिखा है, 'इस घटना के बाद दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और प्रकरण में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि न तो अभी तक इसकी कोई जांच हुई है और न ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है।'

महागठबंधन के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को जूस पिला आमरण अनशन तुड़वाया

राज्य ब्यूरो, पटना

शरद यादव, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी सहित महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। इन नेताओं ने पीएमसीएच में जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए आवश्यक औपचारिकता पूरी करने की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा 26 नवंबर से मिलर हाई स्कूल परिसर में आमरण अनशन पर थे। शुक्रवार संध्या तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी सबके आग्रह पर अनशन समाप्त कर लिया।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए राज्य सरकार आवश्यक औपचारिकता पूरी नहीं कर रही। इसके खिलाफ मेरे आमरण अनशन को महागठबंधन के दलों के अलावा वाम दलों ने समर्थन दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम सभी एकजुट होकर आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कहा कि यह तो ट्रेलर था, शिक्षा में सुधार के लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे। शरद यादव ने कहा कि विपक्ष एकजुट है। हम साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इस बीच भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान भी उपेंद्र कुशवाहा से पीएमसीएच में मिले। उन्होंने कहा कि इस मांग को इनका पूरा समर्थन है।

बेमियादी अनशन के दौरान बीमार पड़े उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को पीएमसीएच में भर्ती थे। वहां पहुंचकर शरद यादव, तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने अनशन खत्म कराया। जागरण

राजद के वरिष्ठ नेता ने जदयू को फिर दिया गठबंधन का न्योता

राज्य ब्यूरो, पटना : राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार में भाजपा को हराने के लिए जदयू और राजद को फिर से एक साथ आने का सुझाव दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र फार्मूले की चर्चा करते हुए कहा कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

पटना में शनिवार को रघुवंश ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की तर्ज पर अगर यहां राजग से नाता तोड़कर जदयू महागठबंधन में आ जाता है तो तस्वीर बदल जाएगी। बिहार में पहले भी ऐसा हो चुका है, जब 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद-जदयू-कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और भाजपा को परास्त कर दिया। इस बार भी भाजपा विरोधी पार्टियां अगर एकजुट हो गईं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। रघुवंश ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक साथ आने में किसी तरह की अड़चन नजर नहीं आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की ओर से ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में ट्रिपल 'ए' फार्मूले पर नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी भाजपा

नईदुनिया, राज्य ब्यूरो, रायपुर

- कांग्रेस सरकार की असफलता, अलोकतांत्रिक और अप्रिय निर्णय को बनाएंगे मुद्दा
- प्रदेश प्रभारी जैन ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव, एक्साइटेड और एक्सपोज करने का दिया मंत्र

भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति तैयार कर दी है। कांग्रेस सरकार की असफलता, अलोकतांत्रिक और अप्रिय निर्णय को मुद्दा बनाकर भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। धान की खरीदी में 2500 रुपये नहीं देना, नगर निगम चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना और शराब की अवैध बिक्री और पूर्ण शराबबंदी नहीं करने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को ट्रिपल ए एक्टिव (सक्रिय), एक्साइटेड (रोमांचित) और एक्सपोज (पर्दाफाश) करने का फार्मूला दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी सक्रिय करेगी। जोश से लबरेज कार्यकर्ता ही चुनाव में जीत दिला सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करने का निर्णय लिया गया है।

भाजपा विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब नगरीय निकाय में प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर उतरने की तैयारी में है। यही कारण है कि पार्टी ने संगठन चुनाव को आधे में रोक दिया। कार्यकर्ताओं की ताकत को नगरीय निकाय चुनाव में पूरा इस्तेमाल करने की तैयारी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने पदाधिकारियों की बैठक में दो टूक कहा कि अब गुटबाजी और तेरा-मेरा की जगह पार्टी उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए काम किया जाए। प्रदेश में 15 साल सत्ता में रहने के बाद पहली बार भाजपा बिना सरकार के नगरीय निकाय चुनाव में उतर रही है। पिछले निकाय चुनाव में महापौर बनाने में भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर थे, लेकिन इस चुनाव में बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में प्रदेश संगठन कोई भी चूक करने को तैयार नहीं है।

भाजपा का वादा निभाओ प्रदर्शन आज : नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले पार्टी धान खरीदी के मुद्दे पर जमीनी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने पर पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ प्रदर्शन करने की तैयारी है। सरकार के धान खरीदी नीति के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक दिसंबर को वादा निभाओ प्रदर्शन करेगी। भाजपा धान ल तोल, नहीं ते हल्ला बोल अभियान के तहत पूरे प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में सारे धान खरीदी केंद्रों में एक दिसंबर को सुबह 11 से चार बजे तक प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिल्हा में प्रदर्शन में शामिल होंगे। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, अपने संसदीय व विधानसभा क्षेत्र में शामिल होंगे।

जागरण संवादी के मंच पर होगा अभिव्यक्ति का उत्सव

जेएनएन, नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी लखनऊ में ही 13 से 15 दिसंबर तक 'संवादी' का आयोजन होने जा रहा है। देश के सबसे ज्यादा पढ़े जानेवाले समाचार पत्र दैनिक जागरण का सालाना उत्सव 'जागरण संवादी' लखनऊ के प्रतिष्ठित भारतेंदु नाट्य एकेडमी में आयोजित किया जाएगा। तीन दिनों तक आयोजित होनेवाले अभिव्यक्ति के इस महामंच पर इस साल साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, राजनीति, थिएटर और फिल्म से जुड़े कई दिग्गज भाग लेंगे। इस दौरान एक हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा।

दैनिक जागरण संवादी के दौरान 'जागरण ज्ञानवृत्ति' के सफल अभ्यार्थियों की सूची भी जारी की जाएगी। दैनिक जागरण के हिंदी को समृद्ध करने के अभियान 'हिंदी हैं हम' के तहत हिंदी में मौलिक शोध के लिए हर वर्ष तीन शोधार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित शोधार्थियों को हर महीने पचहत्तर हजार रुपये दिए जाते हैं। शोध अधिकतम नौ महीने में पूरा करना होता है। इसके अलावा इस वर्ष संवादी के दौरान ही 'दैनिक जागरण सृजन' के अंतर्गत कॉपीराइट बाजार भी लगेगा। जागरण सृजन भी 'हिंदी हैं हम' अभियान का ही हिस्सा है जिसमें किसी लेखक की पहली पांडुलिपि को प्रकाशकों के सामने पेश किया जाएगा। इन नए लेखकों की कृतियों का चयन और उसके प्रकाशन का करार भी कॉपीराइट बाजार के दौरान किया जाएगा।

प्रदूषण हम सबकी चिंता का विषय : राष्ट्रपति

जताई चिंता ▶ रामनाथ कोविंद ने कहा–तकनीक ईजाद करते वक्त रखें पर्यावरण का ध्यान

बोले–तकनीकी क्रांति की चुकाई बड़ी कीमत, कानपुर का प्रदूषण उदाहरण

जागरण संवाददाता, कानपुर

देश के बढ़ते प्रदूषण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जताई है। दो दिवसीय प्रवास पर कानपुर आए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदूषण सबकी चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदूषण के कारकों पर ध्यान खींचा और इससे निपटने के उपाय बताए। प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पीएसआइटी) में रीसेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी पर आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि तकनीकी क्रांति की हमें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। कानपुर का वायु प्रदूषण जीवंत उदाहरण है। तकनीकी ईजाद करते वक्त पर्यावरण का ध्यान रखकर मानव हित में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया कि देश में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

नगर निगम के विशेष सदन में भी राष्ट्रपति ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा कि वर्ष 2017 में उन्हें ईश्वरीगंज में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करने का मौका मिला था। पता चला है कि नगर निगम अब इस अभियान को व्यापक स्तर पर चला रहा है। इन सबके बावजूद दिल्ली में अखबारों के माध्यम से कानपुर के प्रदूषित शहरों में शामिल होने की खबर मिलती रहती है। यह हर किसी की चिंता का विषय है।

मैं दिल्ली में हूं तो मेरे लिए भी, सांसदों-मंत्रियों और हर नागरिक के लिए भी। हालांकि, उन्होंने संतोष जताया कि टेनरियां व सीवर से निकलने वाले अपशिष्ट और कचरे के समुचित निस्तारण की दिशा में काम चल रहा है। बोले, नई तकनीक से इसे और कम किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फार एनर्जी तकनीक का इस्तेमाल करके कचरे से बिजली बनाई जा सकती है। दिल्ली की तरह इमारतों के मलबे की रीसाइकिलिंग करके उत्पाद बनाए जा सकते हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बनाएं शोध व नवाचार का केंद्रः राष्ट्रपति देश के सर्वाधिक छात्र संख्या वाले छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के पहले पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन में शामिल हुए। यहां एक लाख ग्यारह हजार रुपये देकर एनडाउमेंट फंड की स्थापना की। पूर्व छात्रों को इस फंड में सहयोग के लिए प्रेरित किया। कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश को नॉलेज सुपर पॉवर बनाने का है। यह तभी होगा जब शिक्षण संस्थान जिज्ञासा, प्रयोग और कौशल का केंद्र बनेंगे। सभी राज्यपाल विश्वविद्यालयों के संरक्षक का दायित्व निभाने के साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शोध व नवाचार का केंद्र बनाने में योगदान दें। राष्ट्रपति ने कहा कि वे यहां राष्ट्रपति नहीं, पूर्व छात्र की हैसियत से आए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यहां पूर्व छात्र देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, इससे विवि की गरिमा में मानो चार चांद लग गए। कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी थे।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित एल्यूमिनाई मीट में उपस्थित लोगों का अभिवादन करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (बाएं) और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल। संजय यादव

हस्तियों को किया सम्मानित

राष्ट्रपति ने प्रमुख उद्यमी स्व. गौरहरि सिंहानिया को मरणोपरांत अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। उनके भतीजे जेके ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक अभिषेक सिंहानिया ने अवार्ड प्राप्त किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविंद दीक्षित को छत्रपति शाहूजी महाराज अवार्ड दिया। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री नीलिमा कटियार को नारी सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया। सुपर हाउस समूह के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन को उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉ. गौरहरि सिंहानिया अवार्ड से सम्मानित किया। श्री ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल के अध्यक्ष वीरेंद्रजीत सिंह को समाजसेवा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड दिया गया।

दस माह में देश में 128 नक्सली ढेर, दंडकारण्य में सर्वाधिक 78

नईदुनिया, रायपुर

- नक्सलियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने स्वीकार किया
- जारी किया बयान, कहा–मारे गए माओवादियों में 36 महिलाएं भी

देश में 10 महीनों (दिसंबर 2018 से सितंबर 2019) के बीच 128 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया। इसमें से करीब 60 फीसद अकेले दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं। यह स्वीकारोक्ति माओवादियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सीएमसी) ने की है। सीएमसी ने यह भी स्वीकार किया है कि दंडकारण्य के अलावा ओडिशा, आंध्र-ओडिशा सीमा और मध्य प्रदेश- महाराष्ट्र- छत्तीसगढ़ (एमएमसी) में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मारे गए माओवादियों में 36 महिलाएं भी शामिल हैं।

सीएमसी की तरफ से जारी बयान में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव को भी स्वीकार किया गया है। पत्र में केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों और गृहमंत्रालय की बैठकों का भी उल्लेख करते हुए सरकार की रणनीति की चर्चा की गई है। सीएमसी की तरफ से यह बयान गोरिल्ल आर्मी (पीएलजीए) के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर जारी किया गया है। संगठन की तरफ से अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में दो से आठ दिसंबर तक स्थापना दिवस मामले का एलान भी किया गया है।

सुरक्षा बलों पर 360 हमले का दावा, 70 सीधी लड़ाइयां : उक्त दस माह के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर 360 स्थानों पर हमले का दावा किया है। इसमें 70 बार लड़ाई आमने-सामने की रही। दंडकारण्य में किए हमलों में सुरक्षाबलों के 75 जवानों की जान गई। नक्सली ने इन हमलों में 13 हथियार लूटने और 147 को घायल करने का दावा भी किया है। बयान के अनुसार बिहार के दुमका और सारंडा में लंबे समय बाद सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात कही गई है। इस हमले में 10 जवानों की जान गई और 32 घायल हुए थे।

कहां–कितने नक्सली मारे गए

दंडकारण्य	78
बिहार–झारखंड	16
ओडिशा	11
आंध्र–ओडिशा सीमा	14
एमएमसी	08
तेलंगाना	01

(एमएमसी यानी नक्सलियों का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन)

साध्वी प्रज्ञा की दांगी को चुनौती आ रही हूं ब्यावरा, जला लीजिए

नईदुनिया, भोपाल

नाथूराम गोडसे पर संसद में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दिए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बयान से नाराज ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने उन्हें जलाने की धमकी दी थी। अब साध्वी ने ट्वीट कर विधायक को खुली चुनौती दी है। मालूम हो कि साध्वी प्रज्ञा के संसद में दिए बयान के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने गुरुवार को भोपाल में उनका पुतला दहन किया। इस दौरान विधायक दांगी ने कहा कि पुरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर कभी आई तो जला भी देंगे। नईदुनिया ने विधायक से जब बात की तो वे बोले कि अन्यथा नहीं लेना, ऐसे शब्द निकल गए।

'कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है। 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने तक का। राहुल गांधी ने आतंकी कहा और उनके विधायक गोवर्धन दांगी मुझे जलाएंगे। ठीक है तो मैं आ रही हूं ब्यावरा। उनके निवास मुल्तानपुरा पर दिनांक 8 दिसंबर 2019, समय 4 बजे, जला लीजिए।'

–भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट

आजम खान को संसद से क्यों नहीं निकाला गया : साध्वी प्राची

जासं, रुड़की : अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली फायर ब्रांड हिंदू नेता साध्वी प्राची ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा की पैरवी की। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत माता का अपमान करने वाले सांसद आजम खान को संसद से क्यों नहीं निकाला गया। साध्वी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के लोग प्रज्ञा के पीछे पड़े हैं। शनिवार को रुड़की पहुंची साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में संस्कार नहीं हैं। भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बेइज्जती करने वाले लोग संसद में बैठ रहे हैं। साध्वी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के लिए कांग्रेस दोषी है। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का जिम्मेदार भी यही पार्टी है।

दुनिया में साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोग एचआइवी से प्रभावित

विश्व एड्स दिवस से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर एड्स की स्थिति बताने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एड्स से होने वाली मौतों में कमी आई है तो इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह लोगों में इस रोग के प्रति बढ़ती जागरूकता और मेडिकल खोजों को दिया जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद एड्स को लेकर चुनौतियां अब भी बरकरार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार एड्स दिवस की थीम 'कम्युनिटी मेक द डिफरेंस' (समुदाय बदलाव लाता है) रखी है।

विश्व एड्स दिवस (01 दिसंबर) पर विशेष

आंकड़ों में मर्ज का आतंक

- 3.8 करोड़ लोग दुनिया में एड्स के साथ जीने को मजबूर हैं
- 2.4 करोड़ एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं। नौ साल पहले थेरेपी लेने वालों की संख्या महज सवा लाख थी
- 80 लाख लोग नहीं जानते कि वे एचआइवी से प्रभावित हैं

समुदाय आगे आएं

एचआइवी लगातार एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। एचआइवी को रोकने, जांच, इलाज और लोगों की देखभाल के लिए बहुत से स्वास्थ्य कर्मी जुटे हैं। इसके बावजूद गति बहुत धीमी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल जो थीम चुनी है उससे पता चलता है कि जब तक समुदाय एचआइवी/एड्स की रोकथाम के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक यह काम बहुत मुश्किल होगा। डब्लूएचओ ने देशों से अपने कार्यक्रमों में समुदायों को जोड़ने की बात कही है। इससे डॉक्टरों और नर्सों का काम भी घटेगा।

भारत की स्थिति

- 21 लाख लोग एचआइवी के साथ जी रहे थे
- 88 हजार लोग संक्रमित पाए गए
- 69 हजार लोगों की एड्स के कारण मौत (2017 के अनुसार)

मौतों में आई कमी

एड्स के कारण होने वाली मौतों में 2004 की अपेक्षा आधी से ज्यादा कमी आई है। हालांकि उचित समय पर पहचान और बेहतर इलाज के बावजूद पिछले साल 7 लाख 70 हजार लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा भी काफी भयावह है। वहीं 17 लाख नए लोग संक्रमित हुए हैं। 2007 से 2018 के बीच नए एचआइवी संक्रमण में 37 फीसद की कमी दर्ज की गई है और इससे होने वाली मौतों में 45 फीसद की गिरावट आई है।

एचआइवी से एड्स

ह्यूमनोडेफिसिएंसी वायरस (एचआइवी) व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके ध्वस्त कर देता है। इस संक्रमण की सबसे विकसित अवस्था एड्स है। इसका इलाज नहीं कराया जाए तो यह दो से 15 सालों के बीच विकसित हो जाता है।

चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों आरोपित

हैदराबाद, एजेंसियां : महिला पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या और शव को जलाने के चारों आरोपितों को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लोगों के विरोध के चलते चारों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित शादनगर थाने में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अदालत लगाई और दरिंदों को वहीं से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद चारों की मेडिकल जांच कराई गई। सामान्य हालत पाए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। स्थानीय बार एसोसिएशन ने आरोपियों की तरफ से केस नहीं लड़ने का फैसला किया है।

राज्यपाल– केंद्रीय मंत्री परिजनों से मिले: तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। दोनों भरोसा दिलाया कि मामले की जल्द सुनवाई कराकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने परिजनों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं करने और उनके साथ खराब बर्ताव करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा।

दुष्कर्म के बाद जलाई गई नाबालिग ने दम तोड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाई गई 16 वर्षीय नाबालिग की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता नौ दिनों तक बर्न वार्ड के आइसीयू में जिंदगी और मौत से जूझती रही। आखिर में शनिवार सुबह करीब आठ बजे उनकी मौत हो गई। संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को नाबालिग के पड़ोसी ने दुष्कर्म के बाद केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पीड़िता को भर्ती कराया था।

कंबोडिया के सीएम रीप जैसी बसेगी 'इक्ष्वाकुपुरी'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- ग्रीन सिटी के रूप में विकसित होगी अयोध्या, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का देगी संदेश
- नजर आएगा हर वास्तुशैली का मिश्रण, दुनिया पर रहे इक्ष्वाकु वंश के प्रभाव की भी दिखेगी झलक

पावन सरयू नदी के मनोरम तट पर बसी अयोध्या। चलते-चलते कभी दंडकारण्य में प्रवेश कर गए तो कभी पहुंच गए घने विंध्यारण्य में। सहसा वैदिक मंत्रोच्चार आपके कानों में गूंजने लगेंगे और उस तरफ बढ़ते ही यज्ञशाला दिखेगी। गुरुकुल के दृश्य आपको रोक लेंगे। इधर-उधर स्थापित देवालय भक्ति-भाव से विभोर कर देंगे तो भगवान राम सहित इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती राजाओं के भव्य महल रोमांचित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद योगी सरकार अयोध्या में 'इक्ष्वाकुपुरी' कुछ ऐसे ही विकसित करने की तैयारी है, जैसा आपने त्रेतायुग के बारे में पौराणिक कथाओं में पढ़ा-सुना है।

राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को विश्व मानचित्र पर धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की वृहद कार्ययोजना बनाने में जुट गई है। कंबोडिया के आध्यात्मिक-सांस्कृतिक नगर सीएम रीप की तर्ज पर अयोध्या में इक्ष्वाकुपुरी बसाने की तैयारी है। कई दिनों के मंथन के बाद एक कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है, जिसका प्रस्तुतीकरण पिछले दिनों पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किया गया। इसके अनुसार अयोध्या में गुप्तारघाट से ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे तक सरयू नदी के किनारे इक्ष्वाकुपुरी नाम से ग्रीन सिटी बसाई जानी है। सरकार का मानना है कि धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से अयोध्या में वह संभावना है कि हिंदुओं की आस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हो सके। इक्ष्वाकुपुरी के रूप में सरयू के तट पर एक आध्यात्मिक-सांस्कृतिक नगरी की स्थापना विश्वभर के श्रद्धालु व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। इसे विकसित करने के लिए नुजूल, वन और उद्यान विभाग की भूमि का उपयोग करने की योजना है। इस ग्रीन सिटी में निर्मित क्षेत्रफल अधिकतम पांच फीसद ही होगा।

कुछ पैवेलियन बनाए जाएंगे : इक्ष्वाकुपुरी का विकास पूर्व एशियाई हिंदू वास्तुशैली और भारत की तीनों मंदिर (नागर, द्रविड़ और बेसर) वास्तुशैली के मिश्रण से किया जाएगा। भवन निर्माण की अन्य प्राचीन शैलियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ पैवेलियन बनाए जाएंगे। यह दुनिया के उन नगरों की प्रतीकात्मक प्रतिकृति होंगे, जो राम और इक्ष्वाकु वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें रामावती (म्यांमार) और जनकपुर (नेपाल) भी शामिल हैं।

हर राज्य को मिलेगी जमीन : इक्ष्वाकुपुरी में भारत के सभी राज्यों को एक निश्चित क्षेत्र में भूमि आवंटन करने की योजना है। वहां वे राज्य अपने गेस्ट हाउस और प्रमुख धार्मिक स्थलों का मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कर सकेंगे।

सभी प्रमुख संतों के होंगे आश्रम : भारत के सभी प्रमुख संत और आध्यात्मिक केंद्रों को भी भूमि दी जाएगी। वहां उनके शिष्य और अनुयायियों के लिए साधना, अभ्यास, शोध आदि की सुविधा विकसित की जाएगी। बाली (इंडोनेशिया) और अंकोरवाट के आध्यात्मिक केंद्रों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

परियोजना में प्रस्तावित कुछ प्रमुख बिंदु

- चारों वेदों, प्रमुख ग्रंथों, उपनिषदों के महत्वपूर्ण विषयों का ऑडियो-विजुअल चित्रण होगा।
- प्रमुख ऋषियों का जीवन दर्शन बताया जाएगा। गुरुकुल भी स्थापित किए जाएंगे।
- शास्त्रों में वर्णित अरण्य (वन) क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनमें दंडकारण्य, विंध्यारण्य, धर्मारण्य, वेदारण्य आदि हैं।
- शास्त्रों में उल्लिखित सभी जलाशय-सरोवर पुनर्जीवित होंगे।
- इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मनु, इक्ष्वाकु, मान्धाता, रघु, हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, अज, दशरथ, राम की गौरवगाथा आदि का वर्णन विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण का भी मिलेगा संदेश

इक्ष्वाकु वंश की सभी प्रतापी रानियों की जीवन गाथा पर प्रकाश डालने के लिए पैवेलियन बनाया जाएगा। इसमें वेद, शास्त्र और उपनिषदों में वर्णित अन्य विदुषी और प्रभावशाली महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होगा। इससे दुनिया को महिला सशक्तीकरण का भी संदेश देने का प्रयास है।

सुहानी को सर्वश्रेष्ठ महिला कैडेट के लिए ट्रॉफी

महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम फहरा रही हैं। यह साबित कर दिखाया है भारतीय नौसेना की कैडेट सुहानी रामपाल ने। केरल के कन्नूर स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शनिवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पासिंग आउट परेड के दौरान प्रशिक्षु सुहानी रामपाल को सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड महिला कैडेट के लिए जमोरियन ट्रॉफी प्रदान की। प्रेट्र

उत्साह

भगवान राम और मां सीता के साथ दो संस्कृतियों की अभिन्नता फलक पर

सीता–राम विवाहोत्सव के साथ मिथिला के रंग में रंगी रामनगरी

रघुवरशरण, अयोध्या

सुप्रीम फैसले के साथ फलक पर छाए रामलला के बारे में यह जानना रोचक है कि वे महज अपनी जन्मभूमि पर अकेले विराजमान हैं। रामनगरी के अन्य हजारों मंदिरों में उनके साथ उनकी चिर सहचरी सीता का विग्रह अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठित है। वस्तुतः मां सीता और भगवान राम में अभिन्नता प्रतिपादित है। रामकथा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस में यह अभिन्नता इस तरह वर्णित है, गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। यानी भगवान राम एवं मां सीता उसी तरह परस्पर अभिन्न हैं, जैसे वाणी और अर्थ तथा जल और जल की लहर कहने में तो अलग-अलग हैं पर वास्तव में एक हैं।

सीता-राम विवाहोत्सव के मौके पर अभिन्नता की यह विरासत पूरी शिद्दत से शिरोधार्य होती है। उत्सव की इस बेला में अयोध्या अकेले ही नहीं रहती, बल्कि वह रामलला की जन्मभूमि के साथ मां सीता की जन्मभूमि मिथिला के रंग से भी रोशन होती है। रामनगरी का यह चरित्र उसकी आत्मा-अस्मिता में अधिष्ठित है। भगवान राम एवं सीता का अस्तित्व अनादि माना जाता है। रामचरितमानस के वंदना प्रसंग में मां सीता का परिचय प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं- उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। यानी जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन-पोषण और संहार करने वाली हैं। क्लेश हरने वाली हैं, संपूर्ण मंगल को करने वाली हैं। राम जी की प्रिय ऐसी सीता को हम प्रणाम करते हैं। भगवान राम की उपासना का कोई भी संप्रदाय-उप संप्रदाय हो। मां सीता सभी में पूज्य हैं पर रामानुरागियों के कुछ उप संप्रदाय ऐसे हैं, जिसमें मां सीता के प्रति अपूर्व अनुराग परिलक्षित है। रसिक उपासना परंपरा इनमें प्रमुख है। इस परंपरा के नगरी में शताधिक मंदिर हैं। इस परंपरा के उपासक सीता की सखि के भाव से भगवान राम की उपासना करते हैं। हालांकि आराध्य-आराध्या के विवाहोत्सव की रस्म नगरी के सैकड़ों मंदिरों में संपादित होती है। इस क्रम में उन कर्मकांडों और रीति-रिवाजों की पूरे भाव-चाव से पुनरावृत्ति की जाती है, जैसा त्रेता में भगवान राम एवं सीता के विवाह के अवसर पर जनक-जानकी की नगरी मिथिला हुआ होगा। ...तो राम बरात भी निकलती है। उसी भावधारा से स्फुरित होकर, जैसी युगों पूर्व निकली होगी।

अयोध्या के दर्शन भवन में स्थापित भगवान राम व सीता का युगल विग्रह। जागरण

अब संस्कारों के लिए भी अयोध्या पहली पसंद

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां रामनगरी अयोध्या में उत्सवधर्मिता शबाब पर है तो दूसरी ओर संस्कार और उत्सव के लिए भी लोगों की पहली पसंद बन रही है। गाजियाबाद में कक्षा आठ में पढ़ने वाले प्रसून तिवारी को ही ले लीजिए। उनका जन्मदिन 29 नवंबर को पड़ता है। हर बार वे गाजियाबाद में ही अपना जन्मदिन मनाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने तय किया कि इस बार अपना जन्मदिन अयोध्या में मनाएंगे। प्रसून ने माता-पिता व बहन के साथ सरयू नदी में स्नान कर रामलला व बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। फिर सरयू तट पर ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया।

सरयू तट पर ही इलाहाबाद से आए महेश पांडेय मिले। वे अपने नवजात पुत्र के बरही (बरहीं) संस्कार के उपलक्ष्य में अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने सुबह सरयू नदी में स्नान किया और फिर कनक भवन में भगवान का दर्शन-पूजन। रवींद्र तिवारी व महेश पांडेय जैसे कई मिले, जो किसी न किसी उत्सव व संस्कार के सिलसिले में अयोध्या पहुंचे थे।

हनुमानगढ़ी के संत उपेंद्र दास बताते हैं कि संस्कार व उत्सव मनाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह संख्या दिन-ब-दिन बढ़ ही रही है।

21 दिनों में पहुंचे 1.75 लाख श्रद्धालु

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 21 दिनों में पौने दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं, जबकि फैसले के दिन नौ नवंबर को दर्शनार्थियों की संख्या महज 1810 थी। दूसरे दिन यही संख्या बढ़ कर पांच हजार से अधिक हो गई। बीती 11 नवंबर को साढ़े दस हजार से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे थे।

महिला थानेदार के प्रेम जाल में आ फंसा इनामी बदमाश

नईदुनिया, छतरपुर : टीवी सीरियल देखकर मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिला सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री ने इससे मिली तरकीब से एक कुख्यात अपराधी को धर दबोचा। छतरपुर जिले की गरौली पुलिस चौकी प्रभारी माधवी अग्निहोत्री इसके बाद चर्चा में हैं। महोबा (उत्तर प्रदेश) जिले के ग्राम खमा का बालकिशन चौबे (55) कई अपराधों में महीनों से फरार था। पुलिस ने उस पर 10 हजार का इनाम घोषित किया था। उसे पकड़ने के लिए नौगांव के एसडीओपी श्रीनाथ सिंह बघेल के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें गरौली चौकी प्रभारी माधवी अग्निहोत्री सहित कई पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। पुलिस को पता था कि बदमाश बालकिशन चौबे रंगीन मिजाज है। महिला सब इंस्पेक्टर ने उसका फोन नंबर पता किया और राधा बनकर बातचीत शुरू की। बातों में बहलाने के बाद वॉट्सएप से फोटो का आदान-प्रदान भी हुआ। आखिर शादी का प्रस्ताव देकर माधवी ने उसे मंदिर में बुलाया। जैसे ही बदमाश आया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने माधवी को 10 हजार इनाम के साथ ही अन्य पुरस्कार देने की घोषणा की।

13.5 करोड़ के 3डी म्यूजियम की शुरुआत की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसमें राजस्थान विधानसभा के 70 साल के इतिहास को सहेजा जाएगा।

न्यूज गैलरी

जम्मू में पाकिस्तान ने की गोलाबारी, मिला करार जवाब

पुंछ : पाक सेना ने शनिवार को दूसरे दिन भी पुंछ जिले के किरनी शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर गोलाबारी के साथ रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे। इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सीमांत क्षेत्रों के लोगों में दहशत फैल गई। भारतीय सेना ने भी पाक को करारा जवाब दिया। दोपहर बाद साढ़े तीन बजे शुरू हुई गोलाबारी शाम तक जारी रही। इससे पूर्व शुक्रवार देर शाम भी पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ करवाने के लिए गोलाबारी की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम बना दिया था। (जासं)

सीमा पार कर रहे छह बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए छह बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तस्करी को नाकाम करते हुए 1210 बोतल फेंसिडिल और 32 मवेशियों के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की ओर से बताया गया कि गुरुवार रात में चलाए गए अभियान के दौरान उत्तर 24 परगना के बशीरहाट थाना क्षेत्र से छह बांग्लादेशियों को अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर, बागदा थाना क्षेत्र से बीएसएफ जवानों ने एक महिला तस्कर को 10 ग्राम सोना, 50 बोतल फेंसिडिल के साथ गिरफ्तार किया। (जासं)

सियाचिन में हिमस्खलन से दो जवान शहीद, छह को बचाया

हादसा ▶ माइनस 30 डिग्री से कम ताप में बर्फ के तोदों की चपेट में आया दल

पाक के साथ लगती सीमा के पास गश्त कर रहे थे जवान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

समुद्रतल से करीब 18 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में शनिवार को हुए हिमस्खलन में दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जबकि छह अन्य जवानों को समय रहते बचा लिया गया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार सुबह आठ सैन्यकर्मियों का एक दल माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा के पास गश्त कर रहा था। इसी दौरान अचानक हिमस्खलन हो गया और गश्तीदल बर्फ के बड़े तोदों की चपेट में आ गया। सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में हिमस्खलन में गश्ती दल के फंसने की खबर मिलते ही सेना के एवलांच पैंथर्स और माउंटेन रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाके में पहुंची। राहत कर्मियों ने अत्याधुनिक सेंसरों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया और कुछ ही देर में बचाव दल ने छह जवानों को बचा लिया। दो जवानों को गंभीर हालत में बर्फ के नीचे से निकाला गया। ये दोनों करीब 16 फुट बर्फ की मोटी परत के नीचे दबे थे। इन दोनों को मौके पर प्राथमिक उपचार भी दिया गया, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका।

बारह दिन पहले चार सैन्यकर्मी और दो सैन्य कुली हुए थे शहीद : बीते 12 दिनों में सियाचिन में सैन्यकर्मियों के हिमस्खलन की चपेट में आने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व 18 नवंबर को सियाचिन में हिमस्खलन में चार सैन्यकर्मी व दो सैन्यकुली शहीद हो गए थे।

1984 से सियाचिन में पाक के नापाक मंसूबे नाकाम बना रही सेना : सियाचिन ग्लेशियर केंद्र शासित लद्दाख के उत्तरी हिस्से में है। भारतीय सेना वर्ष 1984 से सियाचिन में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने के साथ मौसम से भी जंग लड़ रही है। अब तक सियाचिन में मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के करीब एक हजार सैनिक शहीद हो चुके हैं।

दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है सियाचिन ग्लेशियर : काराकोरम का यह सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 72 किमी है। 18,875 फीट की ऊंचाई से यह ग्लेशियर इंदिरा कोल के पास 11,875 फीट की ऊंचाई पर गिरता है।

तैनात जवान

ग्लेशियर की 110 किमी लंबी एजीपीएल पर दोनों देशों के करीब दस हजार जवान तैनात हैं।

कितनी आती है लागत

इस क्षेत्र में सैन्य चौकी के रखरखाव पर रोजाना का खर्च करीब 3.0 से 3.5 करोड़ रुपये आता है।

मौसम के चलते घातक है पूरा इलाका

दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान अपनी कठिन मौसमीय दशाओं के चलते सैनिकों के लिए जानलेवा बना हुआ है। यहां गोली से अधिक कठिन मौसमीय परिस्थितियों के चलते जवान शहीद होते हैं। 1984 से अब तक यहां करीब 860 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं, 1984 से 1999 के बीच 1300 से अधिक पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है। माइनस 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान और 18-20 हजार फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी सैनिकों के लिए बहुत कष्टकारी साबित होती है।

हताश पाकिस्तान ने फिर रची कश्मीर में हिंसा की साजिश

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कश्मीर में सामान्य होते हालात पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे और वह घाटी में हिंसा भड़काने के लिए साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने गुलाम कश्मीर और अपने विभिन्न शहरों में बैठे कश्मीरी आतंकी कमांडरों को घाटी में अपने कैडर के जरिए आतंकी गतिविधियों में तेजी लाने का हुक्म सुनाते हुए उनके भत्तों पर रोक लगाने की धमकी दी है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर भारतीय चौकियों पर कमांडो कार्रवाई के लिए बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) में कश्मीरी आतंकियों को भी शामिल होने का फरमान सुनाया है। आइएसआइ के इसी निर्देश के बाद से आतंकी कमांडरों ने कश्मीर के धमकी भरे पोस्टर जारी करवाने के साथ दुकानों को आग लगवाकर सामान्य जनजीवन को पटरी पर उतारने की साजिश फिर शुरू दी है।

सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से आतंकी संगठन वादी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए है। इससे आइएसआइ पूरी तरह हताश है। आइएसआइ ने कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए पंजाब, राजस्थान और नेपाल बॉर्डर के जरिए भी आतंकियों और हथियारों को भेजने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रही। सूत्रों ने बताया कि आइएसआइ और पाक सेना के कश्मीर सेल के करीब छह अधिकारियों ने बीते 20 दिनों में गुलाम कश्मीर में दो बार विभिन्न आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ बैठक की है। इन बैठकों में अल-उमर मुजाहिदीन के कमांडर मुश्ताक जरगर के अलावा हसन बन्ना और जमायतुल मुजाहिदीन के जमील उर रहमान के अलावा हिजबुल के शेरखान, एजाज व आमिर ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि हिजबुल के सरगना सलाहुद्दीन के साथ आइएसआइ के अधिकारियों की बैठक रावलपिंडी में भी हुई है। इसी बैठक के बाद सलाहुद्दीन ने जंगल-मंगल कैंप स्थित हिजबुल के ट्रेनिंग कैंप में दो दिन बिताए हैं। इस दौरान सलाहुद्दीन ने कश्मीरी आतंकियों को संबोधित करते हुए उन्हें कश्मीर घाटी में दाखिल होकर जिहादी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए तैयार रहने को कहा है।

कश्मीर में बंद का माहौल बनाने के निर्देश : खुफिया सूत्रों की मानें तो आइएसआइ ने कहा कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में आतंकी कश्मीर में जिहादी गतिविधियां तेज नहीं कर सकते तो उनके सभी वेतन भत्ते और सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कागजों तक सिमट चुके मुस्लिम जांबाज फोर्स और अल जिहाद जैसे आतंकी संगठनों के कमांडरों को भी अपने बचे हुए कैडर को सक्रिय करने के लिए कहा है।

पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाने की साजिश

गुलाम कश्मीर में हुई इस बैठक में आतंकी सरगनाओं ने घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कुछ अन्य लोगों को निशाना बनाने की साजिश को रची है।

आइएस माड्यूल मामले में एनआइए ने तमिलनाडु में छापे मारे

चेन्नई, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आइएस मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में तंजावुर और तिरुचिरापल्ली में शनिवार को दो संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मारे। एनआइए के मुताबिक तंजावुर में अलावुद्दीन तथा तिरुचिरापल्ली के एस. सरफुदीन के आवास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई अन्य चीजें बरामद हुई हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में जून में कोयंबटूर में छापों के बाद मोहम्मद अजरुद्दीन तथा शेख हिदायतुल्ला को गिरफ्तार किया था।

एनआइए ने एक बयान में कहा कि ऐसा संदेह है कि दोनों शख्स जून में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथी हैं। जांच के दौरान दो लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, एक पेन ड्राइव, पांच सीडी/डीवीडी, एक कुल्हाड़ी के अलावा 17 दस्तावेज बरामद भी किए गए हैं। बयान के मुताबिक जब्त चीजों को विशेष अदालत को सौंपा जाएगा और उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।' जांच एजेंसी ने कहा है कि संदिग्धों से इस मामले में दो आरोपितों से उनके संबंधों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ की जा रही है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वे आइएस के लिए किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल हैं।

इस साल 30 मई को एनआइए ने कोयंबटूर के छह आरोपितों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। ऐसी सूचना थी कि उन्होंने तथा उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आइएस की विचारधारा को फैलाया।

'सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता इसलिए पाक लड़ रहा छद्म युद्ध'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 137 वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। एएनआइ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इसमें भी पाकिस्तान को हार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा
- पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 137वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में किया संबोधित

पुणे, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा, पाकिस्तान जानता है कि वह पारंपरिक लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता इसलिए वह छद्म युद्ध लड़ रहा है, लेकिन छद्म युद्ध का यह रास्ता उसे सिर्फ हार की ओर ही लेकर जाएगा।

पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के 137वें कोर्स की पासिंग आउट परेड के अवसर पर राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान को 1948 से लेकर 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों में पता चल गया था कि वह भारत के साथ पारंपरिक या सीमित युद्ध में नहीं जीत सकता। लिहाजा उसने आतंकवाद के जरिये छद्म युद्ध का रास्ता चुना। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकता हूं कि पाकिस्तान को इसमें हार के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। भारत की महत्वाकांक्षा किसी भी देश की जमीन हड़पने की नहीं रही है, लेकिन अगर उकसाया गया तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। राजनाथ ने कहा, 'हम देश के लोगों की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर कोई अपनी जमीन पर आतंकी शिविर चलाएगा या हमले में शामिल होगा तो हमें पता है कि कैसे उसका जवाब देना है।'

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति के संदेश का प्रचार करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने यह भी दिखाया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह आक्रामक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार मानवीय सहायता उपलब्ध कराते हैं, वह प्रशंसनीय है। जब अन्य संस्थान असफल हो रहे हैं या स्वयं को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में एनडीए ही एकमात्र संस्थान है जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है।

284 कैडेट्स ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया

पासिंग आउट परेड के साथ यहां कुल 284 कैडेट्स ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया। पासिंग आउट परेड में शामिल होने वाले अधिकारियों में थलसेना के 188, नौसेना के 38, वायुसेना के 37 और मित्र देशों के 20 कैडेट्स शामिल हैं। विदेशी कैडेट्स भूटान, ताजिकिस्तान, मालदीव, वियतनाम, मॉरीशस, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार से संबंधित हैं। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक कैप्टन मज्जी गिरिधर को प्रदान किया गया। राष्ट्रपति रजत पदक बटालियन कैडेट कैप्टन कुशाग्र मिश्रा और कांस्य पदक बटालियन कैडेट कैप्टन एनके विश्वकर्मा को मिला। 'माइक' स्वाड्रन को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ स्टाफ बैनर प्रदान किया गया।

भारत में दहशत फैलाने को दिव्यांगता को हथियार बना रही आइएसआइ

अंकित गुप्ता, बरेली

- बरेली कैंट में पकड़े गए युवक का भी पाक एजेंट होने का अंदेशा, हो रही पूछताछ
- 2015 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने दी थी 20 युवाओं को ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित कैंट क्षेत्र में जासूसी के शक में पकड़ा गया नेपाली युवक भले ही दिव्यांग हो, मगर वह शातिर बहुत है। उसने अलग-अलग नामों से दो आधार कार्ड बनवा लिए, एक पर नाम है-गंगा बहादुर, जबकि दूसरे में-मोहम्मद मंजर। वह इशारों से खुद को सुनने व बोलने से लाचार बता रहा है, लेकिन उसके पास से दो मोबाइल फोन व दस सिम कार्ड मिले हैं। उससे पूछताछ कर रही आर्मी इंटेलीजेंस और एटीएस ने जब कुछ पुराने मामलों को खंगाला तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। पता चला कि इससे पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसएआइ (इंटर सर्विस इंटेलीजेंस) दिव्यांगों को मोहरा बनाकर जासूसी कराती आई है। अब इस युवक की सच्चाई पता करने में टीमें जुटी हुई हैं। आर्मी से जुड़े सूत्रों की मानें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी दिव्यांगों या इस तरह का नाटक कर पाने वालों को प्रशिक्षित कर भारत भेज रही है। जासूसी के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 2015 के दौरान करीब 20 युवकों को इसकी ट्रेनिंग भी दी थी। पूर्व में सामने आए जासूसी के यह दो मामले इसकी पुष्टि करते हैं।

केस-1: अंबाला में पकड़ा गया था दिव्यांग: हरियाणा के अंबाला में कैंट क्षेत्र से एक युवक को पकड़ा गया था। उसके पास से कई भारतीय नक्शे व सेना से जुड़ी कई जानकारियां मिली थीं। पूछताछ के दौरान सेना को उसके गूंगे बहरे होने की जानकारी मिली थी। चिकित्सकीय परीक्षण में भी इसकी पुष्टि भी हुई थी।

केस-2: मेरठ में जासूस करता था गूंगा होने का नाटक : 2015 में मेरठ क्षेत्र से एसटीएफ ने एक युवक को पकड़ा था। जोकि भारतीय सेनाओं की जानकारी एकत्र कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भेज रहा था। वह बरेली के शाहबाद क्षेत्र में पहचान बदल कर रहा करता था। वह पकड़ा गया तो उसने भी बोल न पाने का नाटक किया था, लेकिन बाद में उसकी असलियत खुल गई थी।

पकड़े गए संदिग्ध युवक से मिला मंत्री की मुहर लगा प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, बरेली : बरेली के कैंट इलाके से पकड़े गए संदिग्ध नेपाली युवक से बरामद सामान में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक के नाम से जारी एक प्रमाण पत्र भी मिला। इसमें लिखा है कि वह गंगा बहादुर, जोकि सरोजनी नायडू मार्ग तोपखाना के निवासी हैं, उनको भलीभांति जानते हैं। पत्र के सबसे ऊपर आधार कार्ड प्रमाणपत्र लिखा है, नीचे बृजेश पाठक के हस्ताक्षर हैं व मुहर लगी हुई है। मंत्री ने इस प्रमाणपत्र को फर्जी बताया। कहा कि, 'मैंने इस तरह का कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है। पूरे मामले की जानकारी कर विधिक कार्रवाई करूंगा।' उधर, एटीएस ने शनिवार को दिन भर साथ रखकर युवक से पूछताछ की। गौरतलब है कि गत मंगलवार को कैंट क्षेत्र से आर्मी इंटेलीजेंस ने एक युवक को पकड़ा था। पूछताछ में उसने खुद को नेपाल का रहने वाला बताया। उसके पास से इंटेलीजेंस ने अलग नाम के दो आधार कार्ड मिले।

रेलिंग विहीन पुलिया से नदी में गिरा वाहन, आठ की मौत

नईदुनिया, बड़वानी (सेंधवा)

- हादसे के शिकार लोग मध्य प्रदेश के निवासी, मृतकों में पांच बच्चे

मध्य प्रदेश की सीमा से 120 किमी दूर महाराष्ट्र के धुले जिले में असंतुलित वाहन रेलिंग विहीन पुलिया से बोरी नदी में गिर गया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। मृतकों में दो महिलाएं और पांच बच्चे हैं।

हादसे के शिकार लोग मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा अंचल के धवल्यागिर (माट्यामेल) के रहने वाले हैं। ये लोग पिकअप वाहन (एमएच 25-पी-3770) में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में खेतों में गन्ना कटाई करने जा रहे थे। शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे धुलिया से करीब 15 किमी दूर बोरी नदी पर बनी पुलिया से वाहन असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। मृतकों छह माह का बच्चा भी शामिल है।

महाराष्ट्र के धुलिया के समीप पुलिया से नीचे गिरा पिकअप वाहन। नईदुनिया

बंगाल में बस-टैंकर में भीषण टक्कर, सात मरे

जासं, मुर्शिदाबाद : बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में तेज रफ्तार तेल भरे टैंकर और निजी बस में हुई आमने सामने की भीषण भिड़ंत में बस व टैंकर चालक समेत सात लोगों की मौत हो गई और करीब 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सवारियों से भरी बस सिलीगुड़ी से बहरमपुर आ रही थी, जबकि टैंकर कोलकाता से असम जा रहा था। हादसा शनिवार तड़के करीब पांच बजे हुआ। दुर्घटना के वक्त अधिकतर यात्री नींद में थे।

गलतफहमी न पालें, जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे सभी कानून : जितेंद्र

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- कहा, अनुच्छेद-370 हमेशा के लिए हट चुका है, अब कभी वापस नहीं आएगा
- कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय कांफ्रेंस शुरू

पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोई गलतफहमी में न रहे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सभी केंद्रीय कानून लागू होंगे। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी उनकी दुकानदारी चलती रहेगी तो वह वे गलत सोच रहे हैं।

कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय रीजनल कांफ्रेंस के पहले दिन शनिवार को जितेंद्र ने कहा कि अनुच्छेद-370 हमेशा के लिए चला गया है। यह कभी वापस नहीं आएगा। अब प्रदेश में सभी केंद्रीय कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार ने फैसला सोच-समझकर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से शरारती तत्व यह शिगूफा फैला रहे हैं कि अनुच्छेद-370 चला गया है, लेकिन जमीन के रजिस्ट्रेशन का पहले वाला सिस्टम बना रहेगा, कुछ दुकानदारों को टैक्स नहीं देना होगा। अवैध खनन का काम चलता रहेगा। इस पर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सारे केंद्रीय कानून लागू होंगे। इन कानूनों को लागू करवाने में लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू हो गया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी लागू होगा। सूचना आयोग के लिए भी काम शुरू हो गया है।

राज्य में पिछले साल हर व्यक्ति पर 27 हजार रुपये खर्च हुए : जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम वेज एक्ट, दहेज पर रोकथाम, शिक्षा का अधिकार कानून समेत सारे केंद्रीय कानून लागू होंगे। पिछले साल केंद्र सरकार ने देश के प्रति नागरिक पर 8027 रुपये खर्च किए, जबकि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक नागरिक पर 27 हजार रुपये खर्च किए गए। कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं मिला।

आपदा प्रबंधन पर मोदी सरकार सचेत : जल शक्ति और आपदा प्रबंधन का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा ही आपदा प्रबंधन को लेकर सक्रिय भूमिका में रही है। केंद्र ने साढ़े पांच साल के कार्यकाल में तापमान में कमी के लिए काम किया है।

9.80 लाख रुपये का चालान

तस्वीर में दिखाई दे रही स्पोर्ट्स कार 'पॉर्शे 911' के मालिक पर अहमदाबाद की पुलिस ने 9.8 लाख रुपये का चालान ठोका है। नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद यह देश में अब तक सबसे ज्यादा जुर्माना है। ट्वीट में पुलिस ने बताया है कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी और न ही कार के कागजात थे। इस कार की कीमत भी करोड़ों में है। कार मालिक ने जुर्माने की राशि जमा भी करा दी है। एएनआइ

बदलाव

सीटें आरामदेह बनाने के साथ शौचालय होंगे सेंसरयुक्त, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेगमपुरा एक्सप्रेस में होगी साज-सज्जा

पांच सितारा होटल जैसे होंगे ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच

जागरण संवाददाता, लखनऊ

रेलवे अब प्रथम श्रेणी वातानुकूलित बोगी (फर्स्ट एसी कोच) के भीतरी डिजाइन को पांच सितारा होटल के कमरों की तरह संवारेगा। सीटें आरामदेह बनाने के साथ शौचालय सेंसरयुक्त बनाए जाएंगे। उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल प्रशासन वाराणसी से जम्मूतवी के बीच चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस की प्रथम श्रेणी वातानुकूलित बोगी की आंतरिक साज-सज्जा बदल रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट है। तीन दिसंबर तक पहली बोगी तैयार हो जाएगी।

लखनऊ मंडल प्रशासन ने कई होटलों के कमरों की भीतरी साज सज्जा का अध्ययन किया था। इसके बाद बेगमपुरा एक्सप्रेस की बोगी के हर कूपे की सजावट का डिजाइन यांत्रिक अनुभाग ने तैयार किया। थीम के आधार पर गैलरी और कूपे में आकर्षक पेंटिंग लगाई जाएंगी, जोकि समय-समय पर बदलती रहेंगी। थीम के अनुसार ही कारपेट के रंग भी बदले जाएंगे। वॉश बेसिन सेंसरयुक्त होगा। साथ ही शौचालय में मॉडर्न शॉवर लगेंगे। शौचालय में वुडेन की फॉल्स सीलिंग और फैंसी लाइटिंग होगी। सीट के ऊपर डिस्प्ले बोर्ड में बोगी के वेस्टर्न और भारतीय पद्धति के शौचालय के खाली होने की सूचना डिस्प्ले होगी। शौचालय की फ्लोरिंग इपाक्सी मैटेरियल से तैयार की जाएगी, जिससे जलभराव नहीं होगा।

ट्रेन के कोच में थीम के आधार पर गैलरी और आकर्षक पेंटिंग लगाई जाएंगी। प्रतीकात्मक

एक कोच पर करीब चार लाख रुपये का आएगा खर्च

रेलवे ने कन्वेंशनल बोगियों को प्रोजेक्ट उत्कृष्ट के तहत संवारने का काम शुरू किया था। चंडीगढ़ एक्सप्रेस, फैजाबाद-दिल्ली और पद्मावत एक्सप्रेस को इसी प्रोजेक्ट के तहत संवारा गया। वहीं, इसी साल काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच की भीतरी सजावट ढाई लाख रुपये से की थी। अब बेगमपुरा एक्सप्रेस में उत्कृष्ट प्रोजेक्ट से भी अच्छी साज-सज्जा की जाएगी। एक कोच पर करीब चार लाख रुपये का खर्च आएगा।

उप्र के बागपत में महज छह दिन सुनवाई में दुष्कर्मी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बागपत

- सवा तीन साल की बच्ची से परिवार के युवक ने किया था दुष्कर्म
- 25 नवंबर से एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई थी

सवा तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले में आरोपित युवक को अदालत ने केस की सुनवाई के छठे दिन आजीवन कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची गत 13 सितंबर की शाम करीब तीन बजे गली में खेल रही थी। दूर का एक रिश्तेदार युवक उसे फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। करीब आधा घंटे बाद युवक बच्ची को लहूलुहान हालत में घर के पास छोड़ गया। बच्ची को चोट लगने की आशंका में परिजन उसे गांव में एक चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने दुष्कर्म की आशंका जताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पिता की तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

पुलिस ने आरोपित को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 30 अक्टूबर को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। 15 नवंबर को पुलिस ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था। 25 नवंबर से एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई।

डीजीसी सुनील पंवार और संयुक्त निदेशक अभियोजन कमलेश कुमार के नेतृत्व में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव तोमर, सुरेंद्र यादव और अनुज ढाका ने पैरवी की। वादी पिता समेत आठ गवाहों की अदालत में गवाही हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित युवक को मामले में दोषी मानते हुए शनिवार को सजा सुनाई।

शीतकाल के लिए बंद हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : उत्तराखंड में प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब सैलानी अगले साल एक अप्रैल से पार्क की सैर कर सकेंगे। इस सीजन में रिकॉर्ड 18 हजार से ज्यादा सैलानी सैलानी पार्क की सैर को पहुंचे। शनिवार को गंगोत्री के पास कनखू बैरियर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधिवत पार्क के गेट बंद किए गए। गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक नंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि इस सीजन में देशी-विदेशी पर्यटकों के कई दलों ने पार्क की सैर की है।

इसके अलावा इस बार सतोपंथ, शिवलिंग, भागीरथी प्रथम, भागीरथी द्वितीय, सुदर्शन, गंगोत्री ग्रुप, जोगिन, माउंट मुम्बा, त्रिमुखी आदि चोटियों के आरोहण के लिए भी कई दल गए थे। उन्होंने बताया कि साल दर साल गंगोत्री नेशनल पार्क में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। इस सीजन में 18,883 पर्यटकों ने गंगोत्री नेशनल पार्क की सैर की, जबकि वर्ष 2018 में यह तादाद 17108 थी।

लंबी रही प्रक्रिया

संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉ राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया।

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

हम भारत के लोग

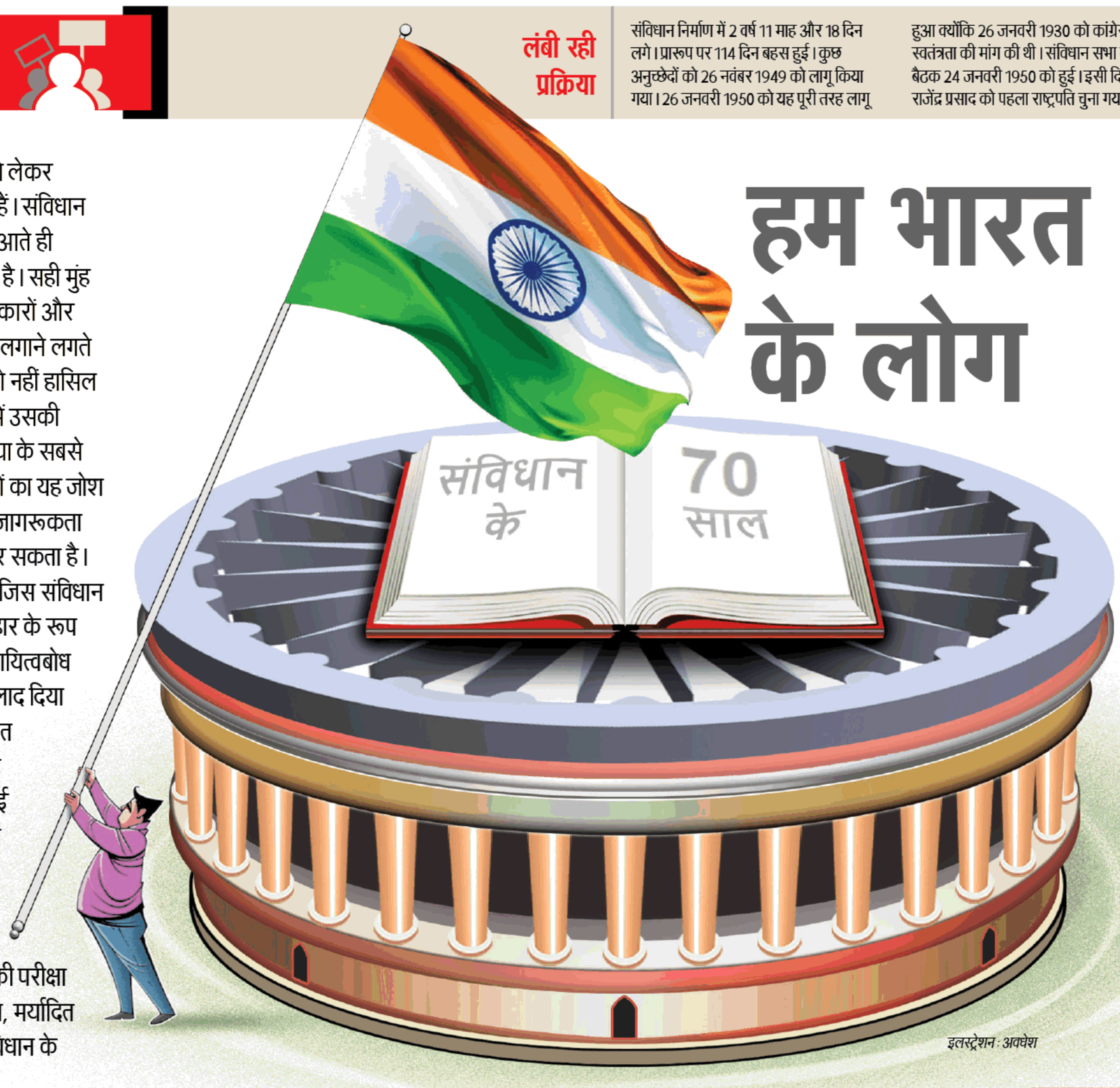

इलस्ट्रेशन : अवधेश

हम भारत के लोग। अधिकारों को लेकर बहुत सतर्क, सजग और चौकस हैं। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की बात आते ही हमारा लहजा शिकायती हो जाता है। सही मुंह और मूड को बुरा सा बनाकर सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं पर तोहमत लगाने लगते हैं। हमें यह नहीं मिल रहा है हमें वो नहीं हासिल है। हमें इसकी आजादी चाहिए हमें उसकी आजादी चाहिए। बहुत खूब। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिकों का यह जोश और जज्बा किसी को भी उनकी जागरूकता की डिग्री पर सोचने को विवश कर सकता है। सोच का दूसरा पहलू भी देखिए। जिस संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों को उपहार के रूप में नवाजा है, उसी ने कर्तव्यों के दायित्वबोध की टोकरी का बोझ भी सिर पर लाद दिया है। कर्तव्यों की बात आते ही औसत भारतीय किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। बगलें झांकने लगता है या कोई कुतर्क करने लगता है। दरअसल बात बड़ी सीधी सी है। संविधान कोई अनोखी बात नहीं करता। जीवन के तमाम पड़ावों से गुजरते हुए हम तमाम संविधानों की परीक्षा देते हैं। संविधान यानी अनुशासित, मर्यादित और शोभनीय आचरण। इस संविधान के कानून कायदों को हम सब बचपन से लेकर अब तक घर, स्कूल, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल आदि पर मानते-अवहेलता करते चले आ रहे हैं। संविधान में उल्लिखित कर्तव्यों का जैसे कोई नागरिक अनुपालन करता है, तो ऐसा करके वह दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों को मुहैया कराता है। मसलन अगर हम सड़क यातायात के नियमों का अनुपालन करते हैं तो किसी दूसरे नागरिक के जीवन के अधिकार को मुहैया कराते हैं। लेकिन हमारे मन-क्रम और वचन में किसी गलत- सही काम करने से पहले देश के संविधान का अक्स कतई नहीं कौंधता। अगर ऐसा हो तो एक के कर्तव्य पालन से दूसरे के मौलिक अधिकार सुनिश्चित होते रहें। हर नागरिक के मन-मस्तिष्क में संविधान की यही छवि-तस्वीर उकेरने के लिए केंद्र सरकार ने जागरूकता अभियान छेड़ा है। विगत 26 नवंबर को संविधान के 70 साल पूरे होने पर शुरू हुआ यह अभियान अगले एक साल तक चलेगा। ऐसे में हम भारत के लोग संविधान को साक्षी मानकर अपने आचार-विचार और व्यवहार में मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का भी संकल्प लें और राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने वाले सजग प्रहरी बनें।

सोच बदलिए, संवैधानिक नागरिक बनिए

योगेंद्र नारायण
पूर्व महासचिव, राज्यसभा

संविधान धार्मिक पुस्तकों जितना ही सम्मान का हकदार है। सामान्य जीवन में हम धार्मिक पुस्तकों में लिखी बात के खिलाफ किसी भी काम को पाप की संज्ञा देते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कार्रवाई को पाप या देशद्रोह मानते हैं? सोचिए।

संविधान राष्ट्र का पवित्र दस्तावेज है। यह उस दर्शन और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर कोई राष्ट्र विकसित होता है और उन लक्ष्यों की पहचान करता है जिन पर देश के नागरिकों की ऊर्जा को निर्देशित किया जाना चाहिए। यद्यपि यह दुखद है कि संविधान को जितना सम्मान और आदर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। हर घर में धार्मिक पुस्तकें जैसे भगवदगीता, रामायण, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान मिल सकती हैं। यह हर एक के धर्म पर निर्भर करता है, लेकिन यह बहुत कम घरों में होगा जहां पर रोजाना पढ़ने के लिए भारत का संविधान होगा। संविधान को वकील, जज जैसे संभ्रांत लोगों का दस्तावेज माना जाता है। यह मीडिया और प्रेस में उस वक्त स्थान पाता है जब राष्ट्रीय राजनीतिक संकट पैदा होता है जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र के मामले में हुआ है। यह वो समय है जब हम अपने संविधान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे नियमित हिसाब ले रहे हों कि हमारे कार्य उसके द्वारा प्रतिपादित आदर्शों के अनुरूप है या नहीं।

संविधान हमारे मौलिक अधिकारों को दर्शाता है। लेकिन गरीब और अशिक्षित सभी प्रावधानों की अनदेखी करते हैं और पुलिस और अन्य अधिकारियों और यहां तक कि अपने शिक्षित भाइयों-बहनों द्वारा शोषण के शिकार होते हैं। यद्यपि यदि ये संवैधानिक प्रावधान हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा व हर स्तर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा थे, तो हर नागरिक को इनके बारे में जानना होगा। यह शोषण और उत्पीड़न को रोकने में मददगार होगा।

हमारा संविधान शिक्षित करता है और जीवन जीने के तरीके को बढ़ावा देता है जो कि हर भारतीय के लिए जरूरी है। यदि हम इन आदर्शों का अनुसरण करते हैं तो यह पूरे देश के लिए उपयोगी होगा। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत उन आदर्शों को आत्मसात किया गया है जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जिनके लिए एक नया मानसिक दृष्टिकोण आवश्यक है। जब यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय या विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और विश्वास यहां तक की अवसर की स्थिति और समानता प्रदान करता है तो साथ ही नागरिकों के लिए आचार संहिता भी उपलब्ध कराता है। यदि हम प्रस्तावना के उद्देश्यों के प्रति अपनी मानसिक सोच को ध्यान में रखते हैं तो यह समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी होगा।

जब संविधान रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है और धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है तो वह महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा होता है और यहां तक की जातिगत बंधनों को तोड़ रहा होता है। संविधान के प्रावधानों से भारतीय समाज के चेहरे को बदला जा सकता है और योग्यता के पनपने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ को नेतृत्व के शीर्ष पदों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

हमारी प्रस्तावना भारतीय संविधान को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित करने के बारे में बात करती है। हम क्यों उम्मीद करते हैं कि सिर्फ सरकार को यह उद्देश्य लागू करना है। हर नागरिक, चाहे वह कोई छोटा व्यवसाय चला रहा हो या अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन, हर किसी को इन आदर्शों को सभी स्तर पर लागू करवाना है। केवल तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जहां अल्पसंख्यकों सहित सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और अपना बेहतरीन दे सकें। लोग कानून अपने हाथों में अगर लेते रहेंगे तो समाज रसातल में चला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रह सकता। यदि यह हमारे नागरिकों के दिमाग में शुरू से ही स्कूलों और घरों से ऐसी सोच हो, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी।

1976 में संसद ने पाया कि जब नागरिक संविधान में प्रदत्त सभी स्वतंत्रताओं का आनंद ले रहे थे उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद संविधान संशोधन के जरिए एक नए अनुच्छेद 51ए को जोड़ा गया। यह नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। ये कर्तव्य संविधान के प्रति सम्मान, समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, पर्यावरण में सुधार और सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकना और व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल करना है। यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें तो यह सभी नागरिकों, सभी समुदायों, सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों और पूरे देश के लिए अच्छा कदम होगा। यह बेहतर जीवन और समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा।

हालांकि यह तभी संभव है जब संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद हमारे युवाओं के अंतःकरण में समाहित हो। संविधान को सजावटी टुकड़े के रूप में रखी जाने वाली किताब के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि इसे हर दिन पढ़ी जाने वाली पूजनीय और पवित्र पुस्तक के रूप में देखा जाना चाहिए।

संविधान के चमगादड़

कुमार प्रशांत
जाने-माने गांधीवादी

हर रोज लगता है कि संविधान एक बड़ा वटवृक्ष है जिसकी शाखाओं पर हम सभी चमगादड़ों-की तरह उलटा लटके हैं; और जो उलटा लटका है उसे कभी कुछ सीधा दिखा है क्या?

क्या आपको मालूम है कि हमारा एक संविधान भी है कि जिसे बनाने में कोई तीन साल लगे और जिसे लिखने में एक आदमकद आदमी ने अपना जीवन-दीप सुखा डाला था? क्या आपको यह भी मालूम है कि इसे बनाने और लिखने में जो लोग जुटे व लगे थे, उनमें से करीब-करीब सभी भारत की आजादी की लड़ाई के तपे-तपाये सिपाही थे जिनकी पूरी जवानी अपने सेनापति महात्मा गांधी के पीछे चलते और लड़ते बीती थी? क्या आपको मालूम है कि अभी-अभी 26 नवंबर की जो तारीख बीती है वही हमारा संविधान दिवस है? और ठीक उसी दिवस पर, संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले महाराष्ट्र के राजनेताओं ने संविधान के शब्दों की और उसकी आत्मा की धुर्रियां ऐसी बिखेरी हैं कि अब संविधान की घायल आत्मा की कराह के अलावा वहां कुछ सुनाई नहीं देता है!

कई बार लगता है, और अब तो बार-बार, हर रोज लगता है कि संविधान एक बड़ा वटवृक्ष है जिसकी शाखाओं पर हम सभी चमगादड़ों-की तरह उलटा लटके हैं; और जो उलटा लटका है उसे कभी कुछ सीधा दिखा है क्या? इस संविधान को बनाने में जिसने सबसे ज्यादा मजदूरी की, उस बाबासाहब भीमराव आंबेडकर ने इसे लिपिबद्ध कर, जब अपनी कलम धरी तभी यह भी कहा कि कोई भी संविधान उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना उसे चलाने वाले लोग होते हैं। और जो कभी पल भर के लिए भी संविधान सभा में गया नहीं, उसका एक शब्द लिखा नहीं, उस प्रक्रिया को कभी तवज्जो दी नहीं लेकिन जिसकी गहरी, विशाल छाया संविधान और उसके निर्माताओं पर पड़ती रही, उस महात्मा गांधी ने बहुत कुरेदने पर कुछ इस आशय की बात कही, 'देश चलेगा कैसे इसकी फिक्र में ये सब दुबले हुए जा रहे हैं, मैं इस फिक्र में पड़ा हूं कि देश बनेगा कैसे! चमगादड़ों, सोचो और बताओ कि जो बनेगा नहीं, वह चलेगा कैसे? जो नहीं बना है उसे ही चलाने की पीड़ा से हम भी गुजर रहे हैं और हमारा संविधान भी! जरा हिसाब तो लगाइए कि हमारा समाज कितनी जगहों से, कितनी तरह से टूटा है? हमारी पुरागाथा का अष्टावक्र भी शरमा जाए इतना विकृत है हमारा समाज जिसमें जातियां मिलती हैं, उप-जातियां मिलती हैं; धर्म और संप्रदाय; अधर्म और जहरीली सांप्रदायिकता; कुसंस्कारी भाषाएं और बोलियां; रीति-रिवाज भी और परंपराएं भी और पतनशील रवायतें भी। ये सब मिलते हैं; और मिलते हैं इन सबसे चिपके हुए उन्मत्त हम लोग; लेकिन जो नहीं मिलता है वह है एक पूरा, खालिस हिंदुस्तानी! जबकि हमारा संविधान जैसे ही बोलना शुरू करता है, एकदम पहला वाक्य ही बोलता है कि हम भारत के लोग अपने लिए यह संविधान बना कर, अपने ऊपर लागू करते हैं। 'हम भारत के लोग'- जो संविधान इससे छोटी किसी पहचान को मानता ही नहीं है, हम बौने लोगों ने उसे ही कितनी जंजीरों में इसे बांध रखा है! इंसान हो कि संविधान किसी को भी बांध देना विकास की, प्रस्फुरण की नहीं बोंसाई बनाने की प्रक्रिया है। बोंसाई, जो प्राकृतिक नहीं है; बोंसाई जो फुलवारियों में नहीं हमारे ड्राइंगरूमों में मिलता है. इसलिए संविधान भी हमें समाज में नहीं, शपथ-ग्रहण समारोहों में मिलता है।

कभी यह बोध जागता है हममें कि जब हम सड़क के गलत किनारे अपनी साइकिल खड़ी करते हैं, जब हम सड़कों को अपनी कारों की पार्किंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब हम सड़क पर पैदल चलते इंसानों को अपनी गाड़ी से हिकारत की नजर से देखते हैं और उनके लिए अपनी गाड़ी किनारे नहीं कर लेते हैं, जब हम सड़क पर थूकते हैं या पान की पिचकारी छोड़ते निकल जाते हैं, और जब हम किसी भी कारण से, किसी भी आदमी या प्राणी पर हाथ या हथियार छोड़ते हैं तब हम संविधान के मुंह पर कालिख पोत रहे होते हैं? अरे चमगादड़ो, संविधान रोज-रोज लोकतंत्र को जीने की कला सिखाने का शास्त्र है; पूजने का और महफिलों में सिर लगाने का ग्रंथ नहीं! चमगादड़ों, संविधान के वृक्ष पर उलटा लटकना नहीं, उसके साथ सीधा खड़ा रहना सीखो!

ऐसे हुआ तैयार

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

कामकाज शुरू

13 दिसंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ सभा की कार्यवाही शुरू हुई। आठ दिन तक उन प्रस्तावों पर बहस होने के बाद सर्वसम्मति से उनको 22 दिसंबर 1946 को पारित कर दिया गया। उसके बाद सभा ने संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया।

परामर्श समिति की रिपोर्ट

परामर्श समिति ने 17 मार्च, 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी गई। उसमें शामिल प्रश्नों के भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। जिसके आधार पर वीएन राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया।

29 अगस्त 1947 को वी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए डॉ भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। 21 फरवरी 1948 को समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में पेश की। पहले और दूसरे वाचन के बाद 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,437 को स्वीकार कर लिया गया। तीसरा वाचन 14-26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया।

जनमत

क्या गलत/सही काम करने से पहले उसके बारे में संविधान की राय हमारे जेहन में कौंधती है?

क्या मूल अधिकारों की रक्षा जितना ही कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति भी सबका संकल्प होना चाहिए?

आपकी आवाज

जिस दिन देश का हरेक नागरिक, संविधान में मिले अधिकारों से ज्यादा मौलिक कर्तव्यों को आत्मसात कर लेगा उसी दिन हमारे देश में सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो जाएगा। **राजेश कुमार चौहान**

सैद्धांतिक रूप से दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हमारे अधिकार किसी अन्य के कर्तव्यों पालन से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः दोनों अंतजीवी हैं। **अमन कुमार**

संविधान के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसके ज्ञान की वृद्धि की कोशिश होनी चाहिए। **गौरीशंकर अंतज**

हमें संविधान का पूरा पालन करना चाहिए। यह आपके अधिकारों को सुरक्षित रखता और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। **मुहम्मद सबीउद्दीन**

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

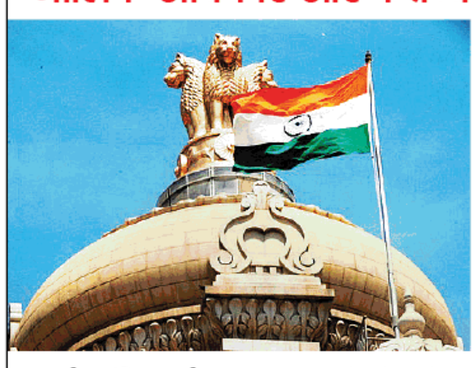

भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'भारत के लोग' से शुरू होती है। यह बताती है कि देश का संविधान देशवासियों के लिए है। लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। हमें मूल रूप से छह मौलिक अधिकार दिए हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।

अधिकारों की मांग, कर्तव्यों से दूर

मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद-51ए में वर्णित हैं। इन्हें 1976 में अपनाया गया।

- संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें।
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें।
- देश की रक्षा करें और समय आने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- समरसता और समान भातृत्व की भावना को बढ़ावा दें।
- हमारी साझी संस्कृति का महत्व समझें और उसे सुरक्षित रखें।
- प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जंगल, झीलें, नदियां और वन्यजीवन आता है कि रक्षा और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना विकसित करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए उच्च स्तर की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।
- बच्चों के परिजन और अभिभावक छह से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं।

भारतीय संविधान : कुछ रोचक तथ्य

भारतीय संविधान अपने आप में अनूठा है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ ही ऐसी कई बातें हैं, जो आपको रोमांचित भी करेंगी तो गर्व से भी भर देंगी।

दो भाषाओं में संविधान की मूल कॉपियां

भारतीय संविधान वास्तविक रूप में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इस हॉल को उस वक्त कांस्टीट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता था।

हस्तलिखित मूल प्रतियां

हिंदी और अंग्रेजी की दोनों मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं। इस तरह से यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भी है।

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिपिबद्ध किया संविधान

संविधान को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य मिला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। उन्होंने होल्डर और निब की सहायता से इटैलिक स्टाइल में कैलिग्राफी के साथ संविधान को लिखा। यह देहरादून में छपा और सर्वे ऑफ इंडिया ने फोटोग्राफ किया।

शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया

संविधान की मूल प्रति को शांति निकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के निर्देशन में सजाया था। वे महात्मा गांधी के काफी निकट थे। प्रस्तावना के पृष्ठ को बी राम मनोहर सिन्हा ने बनाया था।

कहां है मूल प्रतियां

संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में लिखी मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखा गया है। इन प्रतियों को हीलियम से भरे पात्रों में रखा गया है।

संविधान के पहले ड्रॉफ्ट में 2000 संशोधन

संविधान के पहले ड्रॉफ्ट के तैयार होने के बाद इस पर बहस हुई और करीब 2000 संशोधन के बाद मूल संविधान सामने आया।

26 नवंबर 1949 को सामने आया था वर्तमान स्वरूप

संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। आखिरी सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर को इसका फाइनल ड्रॉफ्ट तैयार हुआ।

पौराणिक आराध्यों का जिक्र

संविधान की मूल प्रतियों में हमारे पौराणिक और धार्मिक पात्रों को भी उकेरा गया है। भगवान राम, कृष्ण और शिव को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही उपदेश देते भगवान बुद्ध को भी शामिल किया गया है।

दुनिया के दूसरे देशों से ये है अपनाया

संविधान निर्माताओं ने देश के लोगों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान सौंपने के लिए रात-दिन एक किया। इस क्रम में भारतीय संविधान को संपूर्ण बनाने के लिऐ दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से से बहुत कुछ लिया गया।

फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता

स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्श फ्रांस के संविधान लिया है। हालांकि भारत यह शब्द अपनाने वाला अकेला देश नहीं है। कई अन्य देशों ने भी फ्रांस के संविधान के इन शब्दों को अपनाया है।

ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली

ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था सहित कई बातों को शामिल किया गया।

आयरलैंड से राष्ट्रपति चुनाव

संविधान में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष मतदान का प्रावधान है। यह हमने आयरलैंड से लिया है। इसके साथ ही राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है।

पहले शब्द अमेरिकी संविधान से

भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' से शुरू होती है। हमने इसे अमेरिकी संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे कई प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं।

रूस से मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में मौजूद मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन

संविधान संशोधन और राज्य सभा सदस्यों के चुनाव की प्रणाली को यहां से ली गई।

जर्मनी से मूल अधिकारों का स्थगन

आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की अवधारणा

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 1 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण
मर्यादित आचरण ही व्यक्तित्व को विस्तार देता है

गंभीर सामाजिक समस्या

राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने अश्लीलता के प्रसार को रोकने के लिए सांसदों की एक समिति से कारगर सुझाव देने के निर्देश देकर एक बार फिर एक गंभीर समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया। संचार तकनीक और खासकर मोबाइल फोन के जरिये अश्लीलता का जैसा प्रसार हो रहा है वह केवल संसद ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी गहन चिंता का विषय बनना चाहिए। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि संचार तकनीक के जरिये फैल रही अश्लीलता ने एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले लिया है। यौन अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री सहज सुलभ होना है। चूंकि इंटरनेट पर आसानी से रोक-टोक संभव नहीं है इसलिए बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री भी मोबाइल फोन का हिस्सा बन रही है। हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक न लग पाने पर पहले भी विभिन्न स्तरों पर चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी तक करीब चार सौ वेबसाइट्स प्रतिबंधित की गई हैं और कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें संदेह है कि इससे बात बनने वाली है।

आज जब हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या की खौफनाक घटना पर देश भर में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है तब इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि यह धारणा सही नहीं साबित हुई कि यौन अपराध निरोधक कानून कठोर कर देने भर से दुष्कर्म की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। महिलाओं और यहां तक कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म की तमाम घटनाओं में यह सामने आया है कि अपराधी तत्व मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के आदी थे। कई मामलों में यह भी सामने आया कि अपराधियों ने दुष्कर्म की घटना का वीडियो बना लिया। कुछ मामलों में तो घटना की जानकारी ही तब हुई जब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए। आखिर कोई यह क्यों नहीं समझ पा रहा कि सस्ता मोबाइल डाटा अश्लीलता और अपराध का जरिया बन रहा है? अगर यह माना जा रहा है कि सस्ता मोबाइल डाटा ज्ञान के प्रसार में सहायक हो रहा है तो यह एक खुशफहमी ही है। टेलीकॉम कंपनियों की ओर से सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा का 80 प्रतिशत इस्तेमाल मनोरंजन करने और साथ ही अश्लील सामग्री देखने में खप रहा है। बेहतर हो कि सस्ते डाटा को महंगा किया जाए। इससे दोहरे लाभ होंगे। एक तो सामाजिक समस्या बन गई अश्लीलता का प्रसार थमेगा और दूसरे टेलीकॉम कंपनियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

स्क्रब टाइफस का आतंक

पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता के इर्दगिर्द डेंगू के बाद अब एक और बीमारी के डंक से लोग आतंकित हैं। डेंगू से अब तक राज्य में 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 44 हजार से अधिक लोग पीड़ित हैं। इन सबके बीच स्क्रब टाइफस नामक बीमारी महानगर और कई जिलों के लोगों को चपेट में लेने लगी है। स्क्रब टाइफस से भी अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से अधिक लोग पीड़ित हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस रोग को लेकर विभिन्न अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस बीमारी को लेकर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि स्क्रब टाइफस के लक्षण डेंगू से काफी मिलते-जुलते हैं। इसमें शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। डेंगू की तरह स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीज के रक्त में प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है। एक हफ्ते के भीतर यदि बीमारी का पता चल जाए तो उपचार से पीड़ित जल्द ठीक हो सकता है। यदि देरी हुई तो स्थिति बिगड़ जाएगी और अंग काम करना बंद कर सकते हैं। यदि मरीज का ज्वर कम नहीं हो रहा है तो खून की जांच माइक्रोबायोलॉजी लैब में कराना चाहिए, ताकि बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल सके। यह पहला मौका नहीं है जब बंगाल और खासकर कोलकाता के आसपास के इलाकों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष भी इससे कई लोग पीड़ित हुए थे। हालांकि तब इसे लेकर बहुत चर्चा नहीं हुई थी।

वहीं स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों के लिए डेंगू पहले से सिरदर्द बना हुआ है, ऐसे में स्क्रब टाइफस का मामला सामने आने के बाद परेशानी और बढ़ गई है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को पांच दिनों से ज्वर पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति की डेंगू और स्क्रब टाइफस की जांच कराने की सलाह दी है। बंगाल सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों पर आधारित चिकित्सा नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। स्क्रब टाइफस की मौजूदा स्थिति व लगातार हो रहे संक्रमण से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं डेंगू की तरह से यह बीमारी महामारी जैसी स्थिति पैदा न कर दे। हालांकि, चिकित्सकों का कहना है कि यह लाइलाज बीमारी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ स्वच्छता से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह बीमारी पालतू जानवरों के संपर्क में आने से अधिक फैलती है। इसीलिए स्वच्छता पर जोर देकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है।

भितरघात की शिकार तो नहीं भाजपा

संजय गुप्त

भाजपा को इस पर चिंतन-मनन करना ही होगा कि मोदी-शाह की कामयाब जोड़ी के रहते उसे राज्यों में अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल रही है?

आखिरकार उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद विश्वास मत भी हासिल कर लिया। उन्हें बीते हफ्ते ही इस कुर्सी पर बैठना था, लेकिन इसमें देर इसलिए हुई, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसकी वजह रही राकांपा के अजीत पवार का गुपचुप रूप से उनके साथ आना। फड़नवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बीते शनिवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे राष्ट्रपति शासन हटाया गया। इसके कुछ देर बाद राज्यपाल ने नई सरकार का शपथ ग्रहण करा दिया। यह समाचार सामने आते ही हंगामा मच गया। कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने फड़नवीस सरकार को बुधवार को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। इसके एक दिन पहले ही अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फड़नवीस को भी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा कुछ होने के आसार तभी उभर आए थे जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर विधायक अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के पास चले गए थे। आखिर में खुद अजीत पवार ने भी घर वापसी कर ली।

अजीत पवार ने जिस तरह कुछ ही घंटों के अंदर घर वापसी की और वहां उनका जैसा स्वागत हुआ उससे यही लगता है कि वह ऐसी किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे जिसका मकसद भाजपा को गच्चा देकर उसे नीचा दिखाना था। ऐसा लगता है कि भाजपा के खिलाफ राजनीतिक जाल को बुनने का काम विधानसभा चुनाव के समय ही शुरू हो गया था। भाजपा के लिए यह राजनीतिक जाल जिसने भी बुना हो वह अपने मकसद में सफल रहा। भाजपा ने महाराष्ट्र की सरकार से भी हाथ धोया और अपनी साख भी गंवाई। भाजपा के साथ ही मोदी सरकार के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि आखिर विशेष नियम का इस्तेमाल करते हुए गुपचुप रूप से राष्ट्रपति शासन हटाने की क्या जरूरत थी? ध्यान रहे इस नियम का इस्तेमाल अपवाद स्वरूप और असामान्य परिस्थितियों में किया जाता है। भाजपा के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि सुबह इतनी जल्दी शपथ लेने की क्या जरूरत थी? क्या उसे यह भय था कि कहीं कांग्रेस और राकांपा शिवसेना के पक्ष में राज्यपाल को समर्थन पत्र न सौंप दें? सच्चाई जो भी हो, इन सवालों ने भाजपा को असहज करने का ही काम किया है।

यह सही है कि शिवसेना ने भाजपा के साथ धोखा किया, लेकिन उसे इसका आभास पहले से होना चाहिए था कि चुनाव नतीजे के बाद वह उससे छिटक सकती है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे यही कह रहे थे कि सरकार फड़नवीस

अवधेश राजपूत

के नेतृत्व में ही बननी चाहिए, लेकिन शिवसेना बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गई। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1999 में भाजपा बारी-बारी से मुख्यमंत्री के फार्मूले पर जोर दे रही थी, लेकिन तब शिवसेना इसके लिए उसी तरह तैयार नहीं हुई जैसे इस बार भाजपा नहीं हुई। इसका फायदा कांग्रेस और राकांपा ने उठाया। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, फिर भी सत्ता के लिए एक साथ आ गए। यह गठजोड़ लंबा चला और करीब 15 साल तक शिवसेना को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। 2014 का विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग होकर लड़ा। भाजपा को शिवसेना के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिलीं। वह मजबूरी में भाजपा सरकार को समर्थन देने को तैयार हुई। इसके बाद उसने भाजपा को जली-कटी सुनानी शुरू कर दी। यह सिलसिला लोकसभा चुनाव तक चलता रहा। अमित शाह के मनाने पर वह लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने को तैयार हुई। यह मेल-मिलाप विधानसभा चुनाव में भी बना रहा, लेकिन शायद शिवसेना भाजपा को बड़े भाई की भूमिका में देखने को तैयार नहीं थी और इसीलिए चुनाव बाद वह उससे छिटक गई। उसकी छटपटाहट समझ आ रही थी, लेकिन यह नहीं माना जा रहा था कि वह सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर अपनी कट्टर विरोधी कांग्रेस और राकांपा से हाथ मिलाना पसंद करेगी। उसने ऐसा ही किया। शिवसेना जिस तरह अपने विरोधी दलों के साथ गई उससे भारतीय राजनीति के अवसरवादी चरित्र की ही पुष्टि हुई। अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो शायद यह सब नहीं हुआ होता। जो भी हो, महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम ने यही दिखाया कि राजनीतिक दल जनादेश का मनमाना इस्तेमाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

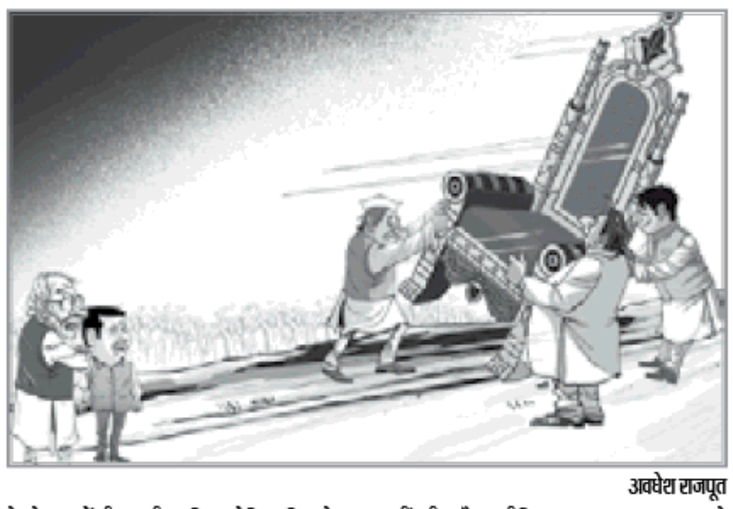

कायदे-कानून से और साथ ही राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से महाराष्ट्र में सरकार भाजपा-शिवसेना की ही बननी चाहिए थी, क्योंकि जनादेश इसी गठबंधन के पक्ष में था। इस जनादेश को ठेंगा दिखा दिया गया। जाहिर है कि इससे वे लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने भाजपा-शिवसेना सरकार बनाने के मकसद से वोट दिए। जब जनादेश की ऐसी अनदेखी होती है तो इससे लोकतंत्र का उपहास उड़ता है और छल-कपट की राजनीति को बल मिलता है। इस राजनीति को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन यह काम तभी होगा जब सभी राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन राजनीति के नियम-कानून तय करेंगे। फिलहाल इसके आसार नहीं हैं।

महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ ही एक और राज्य भाजपा के हाथ से निकल गया। यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस कामयाबी का कारण प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पांच साल तक एक साफ-सुथरी सरकार चलाना और इस दौरान कई बड़े साहसिक फैसले लेना है। दूसरे कार्यकाल में भी यह सरकार साहसिक फैसले लेने में लगी हुई है। दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा साहसिक फैसला अनुच्छेद 370 हटाने का रहा। कुछ समय पहले तक ऐसे किसी फैसले के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यह भी उल्लेखनीय है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में शांति बनी रही। यह किसी उपलब्धि से कम नहीं। ऐसे माहौल में भाजपा को इस पर चिंतन-मनन करना ही होगा कि मोदी-शाह की कामयाब जोड़ी के रहते उसे राज्यों में अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि महाराष्ट्र में भाजपा को अपेक्षित राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकी। राज्य के कुछ इलाकों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के नेता ही मोदी-शाह की जोड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए भितरघात करने में लगे हों? यह वह आशंका है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। वैसे भी अपने देश की राजनीति में सब कुछ संभव है।

response@jagran.com

प्याज महाराज की मनुहार

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

हे सब्जीअधीश्वर, हम तुम्हारी शरण में हैं। हमारी ढीली होती जेब पर कृपा करो और जायके को तृप्त करो

हे भारत भूमि के भोले-भाले भले मानुसों के घर का बजट बिगाड़ने वाले, उच्च बाजार-भाव के मामले में समस्त सब्जियों को पछाड़ने वाले, निर्धन और मध्यवर्गीय जनता की जमी-जमाई गृहस्थी को हिलाने वाले, महंगाई की पीठ पर बैठकर दहाड़ने वाले, अपने दिव्य छिलकायित स्वरूप के ही समान आम आदमी की परत-दर-परत बखिया उधेड़ने वाले और तमाम तरकारियों के तन-बदन पर अपनी दबंग हैसियत का झंडा गाड़ने वाले, बू-धारक, जेब मारक, चमत्कार कारक, हे प्याज महाराज! तुम्हें अनंत बार नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है।

हे महाराज! जो रिश्ता एक मुनाफाखोर का ब्याज से, आगरा का ताज से, अस्पताल का इलाज से, गौरैया का बाज से, आसमान का हवाई जहाज से, कार का गैराज से, नदियों का बैराज से, गवैये का रियाज से, मांझे का पतंगबाज से, ब्यूटी पार्लर का मसाज से, आलसी का कामकाज से, चूहे का अनाज से, नवयौवना का लोकलाज से, दशानन का रामराज से और आत्मकेंद्रित व्यक्ति का समाज से है, वही रिश्ता एक आम आदमी का प्याज से है। इन सहज संबंधों के ध्वस्तकारक, नित्य नवल उच्च दर विहारक, हृदयविदारक हे प्याज महाराज! तुम्हें असंख्य बार नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है।

हे अपना नाम स्वयमेव शतकवीर धरने वाले, महंगाई के सभी पुराने कीर्तिमानों को तहस-नहस कर नया रिकॉर्ड कायम करने वाले, दूर रहकर हाथ लगाए और छीले बिना ही हर किसी की आंख में आंसू भरने वाले, किसी चतुर-सुजान नेता की मानिंद आज की तारीख में कल के किए हुए अपने ही वादे से मुकरने वाले, हद की सरहद के पार के भी उस पार से गुजरने वाले, अपने लच्छेदार शरीर के माफिक हमारे नोटों को लच्छा-लच्छा कुतरने वाले और बाजार की कीमतों के एवरेस्ट पर चढ़कर नीचे न उतरने वाले, सलाद संहारक, उधार कारक, गृहदशा बिगाड़क, हे प्याज महाराज! तुम्हें अनगिनत बार नमस्कार है।

हे गोलमटोल तनधारी, नखराकारी, एक गरीब ने तुम्हें हाथ लगाना चाहा, उसे बिजली जैसा करंट लगा। एक मजदूर ने दुकानदार से तुम्हारा भाव क्या पूछ लिया, उस सब्जी वाले के चरणों में गिरकर वहीं पर संज्ञाशून्य हो गया। टमाटर और अन्य फल-सब्जियां निरंतर तुम्हारा पीछा कर रही हैं, मगर तुम्हें छू पाना तो दूर, वे तुम्हारे भाव के आसपास तक पहुंच पाने को तरस रही हैं। तुमको जिस किसान ने अपना खून-पसीना एक समझकर रात-दिन की कड़ी मेहनत से उगाया, तुमने उसके भी होंठों से लगने से इन्कार कर दिया। बेचारे सेब तक को सलाद के रूप में कटना पड़ रहा है और तुम दूर खड़े होकर अट्टहास कर रहे हो। किचन के उपहासक, सब्जी बाजार और मंडी के विकट विनाशक, हे प्याज महाराज! तुम्हें कोटि-कोटि नमस्कार है। हे देव, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आयात में भी तुम हो। निर्यात में भी तुम हो। गंध में भी तुम ही। संबंध में भी तुम ही हो। तुम बारहमासी हो। तुम नासिक से नासिका तक के निवासी हो। आपकी महिमा अपरंपार है।

हे सब्जियों के अधीश्वर, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हमारी ढीली होती जेब पर अपनी कृपा। हमारे घर पधारो और हमें सस्ती उपलब्धि का आशीर्वाद प्रदान करो। तुम्हारी महिमा गाने की क्षमता हमारी सामर्थ्य से बाहर है। तुम इन दिनों सर्वत्र समाचार में हो। आजकल तुम ही जन-जन की जिह्वा पर विराजमान हो। अब आओ और हमारी जिह्वा पर साक्षात अपने चरण धरो। हे गंध देव, हम तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि हमारी रसोई का एकमात्र अवलंब तुम ही हो। तुम्हारे बिना स्वाद की कल्पना भी निरर्थक है। तुम रोटी के साथ गठबंधन कर दीन-दुखियों को क्षुधातृप्ति देने वाले अनादि देव हो। तुम बर्गर आदि फास्ट फूड के मध्य अवस्थित होकर युवा पीढ़ी को अनंत ऊर्जा प्रदान करने वाली महाशक्तियों में वरेण्य हो। शंख स्वरूप, शाक-सब्जियों के भूप, दोप्याजा सुशोभक, छौंक बघारक, कर्णशूल हारक हे प्याज देव! तुम्हें शत-शत नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है। प्रभु अब तो आपकी महिमा इतनी बढ़ गई है कि हीरों के शहर में भी चोर हीरे लूटने के बजाय आपसे भरी एक बोरी चुराकर भागने में ही ज्यादा भलाई समझने लगे हैं।

response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति मार्ग

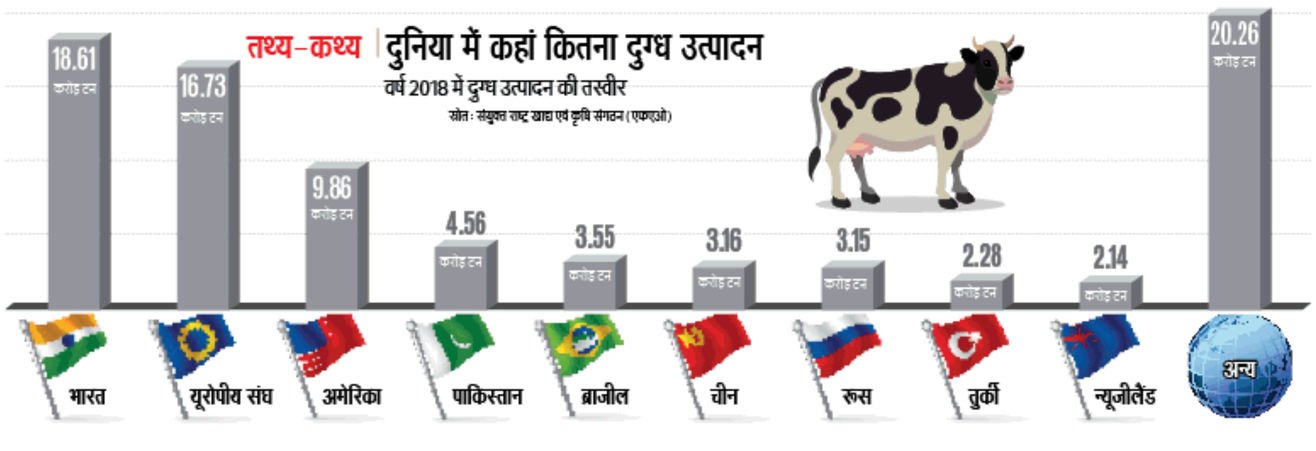

समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान ईश्वरीय चेतना से एकाकार होने को ही योग कहते हैं। इससे मनुष्य अपने मन को स्थिर करके आत्म-साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं। जैसे ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग। ये सभी मार्ग ईश्वर चेतना तक पहुंचने के साधन हैं! ज्ञान योग में उपासक अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी मांग बनाकर निर्गुण ब्रह्म से जुड़ने का सीधा प्रयास करता है! यह काफी कठिन मार्ग है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इसमें भटकाव की आशंकाएं भी अधिक होती हैं!

भक्ति मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अपनी सारी व्यथा अपने आराध्य देव को सुनाकर स्वयं अपने हृदय में हितकारी सलाह का अनुभव करता है! इस प्रकार वह अपने आराध्य देव रूपी संरक्षक की देखरेख में अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है! इसमें सफलता प्राप्ति की प्रचुर संभावनाएं होती हैं! सर्वविदित है सभी योग मार्गों का एकमेव लक्ष्य परम ब्रह्म की प्राप्ति ही है। इसी कड़ी में भक्ति मार्ग पर चलने वाला भक्त भी काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकारों की सेना पर विजयश्री का वरण कर आखिर में समस्त ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त निरंकार ब्रह्म से ही जुड़ जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि सीधे ज्ञान मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को उस प्रकार का सहारा नहीं मिलता जैसा एक भक्त को अपने आराध्य देव के रूप में प्राप्त होता है! सांसारिक जीवन में तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब हमारी इंद्रियां हमें भटकाव की ओर उन्मुख करती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य में आस्था और विश्वास एवं उनसे जुड़े मूल्य ही हमें सही पथ पर आबद्ध रखते हैं। ऐसी स्थितियों में भक्ति मार्ग ही हमारी हिचकोले खाती नैया का बेड़ा पार लगाता है।

इस समूचे विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वह अपनी दिनचर्या में ईश्वर भक्ति को शामिल करे। इस प्रकार ईश्वरीय चेतना सदैव उसके साथ रहती है। यही चेतना उसे इंद्रिय भोग के दुष्प्रभावों से बचाते हुए जीवन में सफलता दिलाती है।

कर्नल शिवदान सिंह

मिसाल बने अनोखे पुल

मुकुल व्यास

मेघालय में उफनती नदियों को पार करने के लिए रबर की जड़ों से बने टिकाऊ पुल आधुनिक वास्तुशिल्प का हिस्सा बन रहे हैं

पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में घने जंगल, दुर्गम घाटियां और बीहड़ हैं। यहां की छोटी-छोटी पहाड़ी नदियां मानसून के दौरान उफनती रहती हैं। बारिश की अधिकता के चलते यहां लकड़ी के पुल बहुत जल्द गलने लगते हैं या बह जाते हैं। स्टील और कंक्रीट से बने पुलों की भी सीमाएं हैं, लेकिन जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनाए गए पुल सदियों तक चल सकते हैं। म्यूनिख की टेक्निकल यूनिवर्सिटी (टीयूएम) के प्रो. फर्डिनांड लुडविग ने इन अनोखे पुलों के अध्ययन के बाद इस असाधारण कला को आधुनिक वास्तुशिल्प में शामिल करने का सुझाव दिया है।

राज्य की इन उफनती हुई नदियों को पार करने के लिए स्थानीय खासी और जयंतिया आदिवासियों ने रबर पेड़ की जीवित जड़ों से पुल बनाए हैं जो बेहद मजबूत और टिकाऊ हैं। टीयूएम में लैंडस्केप आर्किटेक्चर के प्रोफेसर लुडविग का कहना है कि 'फाइकस इलास्टिका' नामक पेड़ की जड़ों से बने इन पुलों की लंबाई 50 मीटर तक पहुंच सकती है और ये सैंकड़ों वर्षों तक टिके रह सकते हैं। उन्होंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में वनस्पतिशास्त्र के प्रोफेसर थॉमस स्पेक के साथ मिलकर ऐसे 74 पुलों का विश्लेषण किया है। लुडविग के अनुसार इन पुलों की काफी हुई है, लेकिन इनकी वैज्ञानिक पड़ताल बहुत कम हुई है। टीयूएम में वास्तुशिल्प विभाग के प्रोफेसर विलफ्रिड मिडलटन का कहना है कि पारंपरिक खासी निर्माण तकनीकों के बारे में अभी तक लिखित रूप से ज्ञान उपलब्ध नहीं था।

शोधकर्ताओं ने इन पुलों की निर्माण प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए पुल निर्माताओं से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने इन जटिल संरचनाओं के हजारों फोटो खींचे जिनके आधार पर पुलों के थ्री डी मॉडल तैयार किए। शोधकर्ताओं के दल ने पहली बार इन पुलों की जगहों के नक्शे भी तैयार किए। पुलों के निर्माण की प्रक्रिया वृक्षारोपण से आरंभ होती है। स्पेक ने बताया कि पुल बनाने वाला व्यक्ति नदी के किनारे या बीहड़ के छोर पर फाइकस इलास्टिका का पौधा लगाता है। धीरे-धीरे यह पौधा बाहरी जड़ें विकसित करने लगता है।

इन जड़ों को बांस या पाम के तनों से बने ढांचे में बुना जाता है। इन्हें नदी के ऊपर दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन 'हवाई' जड़ों के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद उन्हें रोप दिया जाता है। ये जड़ें छोटी-छोटी जड़ें विकसित करती हैं। इन जड़ों को भी किनारे की तरफ मोड़ कर रोप दिया जाता है। पौधे की निरंतर वृद्धि और जड़ लपेटने की तकनीकों के उपयोग से फाइकस इलास्टिका की जड़ें जटिल संरचनाओं में बदल कर टिकाऊ और सुरक्षित पुलों का निर्माण करती हैं। नई स्फुटित होने वाली जड़ें मौजूदा ढांचे में निरंतर रूप से जुड़ती रहती हैं। इन जीवित पुलों को पूरा करने में कई दशक लग जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया में अक्सर कई पीढ़ियां शामिल होती हैं। प्रो. लुडविग का कहना है कि खासी लोगों की पारंपरिक तकनीकों के बारे में नए अध्ययन से आधुनिक वास्तुशिल्प के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

शिष्टाचार में भी सियासत

चुनावी माहौल में विरोधी राजनीतिक दलों के खेमों में तल्खी अपने चरम पर होती है। फिर भी यह देखना बहुत रोचक होता है कि आम कार्यकर्ताओं में तनातनी के बावजूद शीर्ष नेता बड़े सौहार्द के साथ एक दूसरे से मेल-मुलाकात करते हैं। यह सब आम जनता से नजरें छिपाकर किया जाता है। ऐसी मुलाकातों के लिए सबसे माकूल स्थान होता है हैलीपैड। दरअसल चुनावी दौर में लगभग हर बड़े नेता रोजाना सुबह हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं। विधानसभा चुनावों के सिलसिले में इन दिनों झारखंड में रैलियों का जोर है। ऐसे ही एक दिन जब झामुमो के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन हवाई अड्डा पहुंचे तो वहां मौजूद भाजपा के कुछ सांसद और विधायक खड़े हो गए। वैसे तो यह शिष्टाचार था, लेकिन राजनीतिक बढ़त बनाने के लिहाज से हेमंत ने कहा-अरे अभी से खड़े मत होइए, वक्त आने दीजिए। तत्काल भाजपा नेताओं को अहसास हुआ कि सोरेन शिष्टाचार में भी सियासी दांव लगा गए और वे तुरंत उठ खड़े हुए।

खा गए मात

एक कहावत है कि दूर के फायदे के लिए नजदीकी लाभ को अनदेखा किया जाता है, लेकिन अगर इस चक्कर में कोई बड़ा मुद्दा ही पीछे छूट जाए तो वापसी के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कांग्रेस के साथ भी बीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। गोडसे को देशभक्त कहने के विवाद पर भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के माफी मांगने से एक दिन पहले सुबह से ही कांग्रेस लोकसभा में विरोध के लिए तैयार थी। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने इसका विरोध जताना शुरू किया। स्पीकर की ओर से ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने पर कांग्रेस ने तुरंत सदन से बहिष्कार कर दिया। पूरा मामला पांच मिनट में ही निपट गया और उसके बाद पूरा प्रश्न काल हुआ, लेकिन कांग्रेस के कुछ रणनीतिकारों ने इसे सदन में पार्टी के नेता की कमजोर रणनीति बताया। शायद यही वजह रही कि अगले दिन पार्टी को इस मामले में पूरी ताकत दिखानी पड़ी जिसके बाद भाजपा सांसद को दो बार माफी मांगनी पड़ी।

गुरु-चेले का खेल

राजनीति में अपने गुरु को ही पटखनी देने के किस्से इन दिनों सियासी गलियारों में खासे चर्चा का विषय हैं। वजह स्वाभाविक तौर पर अजीत पवार का अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार को दिया झटका है। भतीजे ने जिस तरह गच्चा दिया उसके बाद सियासत के ऐसे पुराने किस्सों की खूब चर्चा है। संसद के गलियारे में चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी एक मिसाल का जिक्र करते हुए सांसदों की एक टोली ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सीएम रमेश पर व्यंग्य-बाण चलाए। दरअसल रमेश ने भी लोकसभा चुनाव के बाद अपने राजनीतिक गुरु चंद्रबाबू नायडू को गच्चा देते हुए चार राज्यसभा सांसदों को तोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। दिलचस्प बात यह थी कि रमेश ने चंद्रबाबू को अपना गुरु तो स्वीकार किया, मगर यह भी कहा कि वह गुरु के सियासी उत्तराधिकारी थे। मगर बाद में गुरु के इरादे बदल गए और वह अपने बेटे नारा लोकेश को आगे बढ़ाने लगे। ऐसे में गुरु को झटका देने के अलावा भला रास्ता भी क्या था। सियासत में गुरु और चेले के खेल की कहानियों का सार यही है कि समय रहते अगर दोनों में से कोई एक दूसरे का सियासी इरादा सही समय पर नहीं भांप पाया तो राजनीतिक बत्ती गुल होनी तय है।

उम्मीद से ज्यादा

बंगाल की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने के एक दिन पहले संसद भवन में तृणमूल सांसद पत्रकारों से बात कर रहे थे। किसी ने पूछ लिया कि परिणामों को लेकर आपकी क्या उम्मीद है। सांसद महोदय ने कहा कि एक सीट पर हम जीतेंगे और एक सीट भाजपा के खाते में जाएगी। तीसरी सीट किसी भी पार्टी के पाले में जा सकती है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वोटिंग हुई है। यानी सांसद महोदय को अपनी पार्टी की एक सीट पर जीत को लेकर ही भरोसा था। खैर जिस दिन नजीते आए तो उनका अनुमान एकदम उलट हो गया। तीनों सीटें तृणमूल के खाते में चली गईं। जिस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी वहां भी उसे जीत नसीब नहीं हुई। खैर, अगले दिन सांसद महोदय को पत्रकारों ने फिर पकड़ा। तब उनके तेवर एकदम बदले हुए थे। वह बोले कि हमें तो पहले से ही मालूम था कि तीनों पर हमारी जीत होने जा रही है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।